संभव सहायता प्रदान की जा रही है। घटना के बाद तुरंत एनडीआरएफ की दो टीमें, भारतीय सेना की दो कॉलम्स और दो आईएएफ हेलिकॉप्टरों को खोज और बचाव अभियान में लगा दिया गया है। तीन बेली पुलों के निर्माण के लिए सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के कॉलम तैयार किए गए हैं, जो चार बजे तक साइट से रवाना हो जाएँगे। एनडीआरएफ, सेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस और स्थानीय इमरजेंसी रेस्पोंस टीम की 300 से अधिक बचाव कर्मियों को बचाव और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया है। तलाशी और बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की तीन अतिरिक्त टीमें मार्ग में हैं। खोज और बचाव अभियान के लिए dog squad को भी तैनात किया गया है। सेना के डीएससी सेंटर कन्नूर की दो टुकड़ियाँ रास्ते में हैं तथा त्रिवेंद्रम की 91 इंफेंट्री ब्रिगेड की दो टुकड़ियाँ स्टैंडबाय में हैं, उन्हें हवाई मार्ग से कोझीकोड पहुँचाया जा रहा है। भारतीय सेना के दो हेलिकॉप्टरों को बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण वे उस क्षेत्र में उतरने में असमर्थ हैं। यह प्रयास जारी है कि सेना की दो हेलिकॉप्टर्स वहाँ पहुँच सकें। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज़मोरिन को क्षतिग्रस्त पुल की दूसरी ओर बचाव श्रमिकों की भूमि की आवाजाही स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैनात कर दिया गया है। आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त संसाधन भेजे जाएँगे। उच्चतम स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24x7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केरल के भूस्खलन प्रभावित लोगों के बचाव के लिए मोदी सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

GENERAL DISCUSSION-*Contd.*

The Union Budget, 2024-25
and
The Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir, 2024-25

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. V. Sivadasan.You have five minutes.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Mr. Chairman, Sir, the Budget should not be a tool for the betrayal of the people. But, as one goes through the Budget document, we find that this Government is betraying the people. This Budget is against the federal spirit of the country. And, it is also trying to inject the venom of enmity between the States of this great Republic.

The grants-in-aid, allocated to the State, are less than the last year's Budget estimate. The State, including Kerala, demand justice from the Union Government. In

India, majority of the people depend upon the agriculture, which is an unorganized sector. And, what has been given to them in this Budget?

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

Peasants and the workers are on the streets. किसान और मजदूर अभी संघर्षों के रास्ते में हैं। They want more allocation for fertilizers and energy. But, you have reduced Rs. 46,270 crore from the allocations for the fertilizers. Sir, they have reduced the allocations to the Power Ministry. The reduced amount is Rs. 24,000 crores. They have reduced Rs. 49,254 crores from the allocation for the rural development. They have given huge publicity on Crop Insurance Scheme, Nadda*ji* is here. For the Crop Insurance Scheme, Rs. 400 crores have been reduced by this Government. When States demand something from the Union Government, then, the Union Government blames the State. They say that the States have not submitted the accounts. What is the status of the MGNREG — the lifeline project of the nation, the lifeline project of rural India? The agricultural workers are struggling for more allocation. They demanded minimum two lakh crores for MGNREG scheme. But the allocated amount is only Rs.86,000/- crores. Earlier, Rs.86,000/- crores had been allocated but even that has been reduced. Is it because of the non-submission of accounts. Sir, I wish to recite a stanza from a Malayalam poem, the English translation of which is: "I hear the cry of crores of God in the cry of a little child." एक बच्चे के आंसू में मुझे करोड़ों देवताओं के आंसू दिखते हैं। Sir, this Government did not hear the cry of the people. This Government has not intervened in the issues of children. They have not increased a single rupee for child welfare. I do not know whether it has any connection to the statement of a person that his birth is not a biological one. Saksham Anganwadi and POSHAN allocations have been reduced. The Government is saying that our country has become an economic super power. But they are not increasing the wage of anganwadi workers. How cruel it is! Why are you not ready to give minimum Rs.15,000/- per month for anganwadi workers? The Government is saying that our country has become an economic super power. But they are not increasing the wage of Mid Day Meal workers in our country. How cruel, Sir! They have given only Rs.1,200/- per month wage for Mid Day Meal workers. It is a matter of shame. They have reduced the allocations to the Mid Day Meal and PM-POSHAN.This Government has completely neglected the needs of the people of all age groups. The Government is saying that our country has become an economic super power. But, you are not increasing a single *paisa* for the ASHA workers. They are working for the nation; they are working for the people. But the Government is not ready to increase

the wages of ASHA workers. The Government is saying that our country has become an economic super power, but they are not increasing the old-age pension. You are not paying even the two hundred rupees on time. They told us that they will create two crore jobs every year. But they are not making appointments to the vacant posts. About 12 lakh posts are lying vacant in various departments. They told us about the importance of atomic energy but they have reduced the allocation to BARC. They are telling us about the importance of health sector but they have reduced the allocation for health sector including the funds for National AIDS and STD Control Programme. They keep telling '*beti bachao*' but in this Budget, the allocation for women safety has been reduced. This Budget is the Budget of contradiction. Sir, ultimately, this Budget is the betrayal of the people. Growth and development are different. Growth is important but development is essential. The equitable distribution of resources is essential for development of nation, for protecting the economic democracy. Growth without development is meaningless and unjust. सर, श्री राम ने सत्य के लिए सत्ता का त्याग कर दिया, लेकिन कुछ लोग राम के नाम पर सत्ता पाकर सत्य को मार रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Conclude, please.

DR. V. SIVADASAN: Sir, two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; whatever the hon. Chairman has permitted; you will have to finish in that.

DR. V. SIVADASAN: Sir, one minute.

One day, truth will win; one day, the people will win. *Satyamev Jayate*.

Sir, I would like to add only one thing. Today, in Wayanad in our State, one huge disaster has happened. So, Disaster Management Response Team in the Centre is very necessary. The Centre will provide more money for setting up a Disaster Management Team to help the State for development of disaster management infrastructure.

4.00 P.M.

श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा (सिक्किम): माननीय उपसभापति महोदय, 23 जुलाई, 2024 को माननीय वित्त मंत्री, निर्मलासीतारमण जी ने देश का जो बजट पेश किया है, उसका मैं आंतरिक हृदय से स्वागत करते हुए अपनी दो-चार बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री

जी, साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी को सिक्किम की जनता की तरफ से आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस बजट में सिक्किम के बारे में भी ज़िक्र किया गया है। इस बजट में जितना दिया हुआ है, विशेष करके नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स के बारे में और ट्राइबल के बारे में लिखा हुआ है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि आने वाले 5 साल में अवश्य ही नॉर्थ-ईस्ट का डेवलपमेंट होगा। इस सदन में विशेष कर जो मुद्दा उठा हुआ है, उसमें educated unemployment, बेकारी समस्या के बारे में ज्यादा चर्चा हुई है। इसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बेकारी की समस्या, जो सिर्फ राज्य और देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह global phenomenon - यह इस संसार की समस्या है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी पढ़े-लिखे भाई-बहन हैं, चाहे वे राज्य में हों, चाहे वे जहां भी हों, सरकार की तरफ से उन लोगों को, विशेषकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईटीआई या अन्य कोई ट्रेनिंग देने से बेकारी की समस्या हल हो सकती है। महोदय, एक कहावत है कि जिसके पास शिल्प है, जिसके पास कला है, वह भाई अथवा बहन जहां भी है, वहीं रह कर अपनी जिंदगी चला सकता है। पढ़ने का उद्देश्य - जो सर्टिफिकेट होल्डर है, मैं समझता हूं कि वह सर्टिफिकेट सिर्फ एक क्राइटेरिया है, लेकिन उसके पास जो कला है अथवा उसके पास जो भी क्षमता है, उसके होने से वह कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है, कहीं भी रहकर वह अपनी जीविका चला सकता है। इससे यह मालूम होता है कि जो बेकारी की समस्या है, इसका हम आसानी से समाधान कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पढ़ने का उद्देश्य बेकारी की समस्या पैदा करने के लिए नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य यह है कि ओवरऑल - शारीरिक और मानसिक डेवलेपमेंट हो। यह हमारे लिए जानना जरूरी है। यह बेकारी की समस्या, यह पोजिशन, अपोजिशन की बात नहीं है, इसका सामना हम सबको मिलकर करना है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बजट बुक में इस बार हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने दिया हुआ है, इससे यह लगता है कि अवश्य ही जिस तरह से काम फाइल में नहीं, फील्ड में होने से देश की तरक्की होगी, यह मैं समझता हूं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से वे थर्ड टर्म सरकार चला रहे हैं, सरकार बनाई हुई है और जिस तरह से काम हो रहा है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अवश्य ही हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा और देश में डेवलपमेंट होगी। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। जैसा हमारा सिक्किम है। वहां एनडीए गर्वनमेंट आने के बाद सिक्किम में चारों तरफ विकास हुआ है, मैं यह इस सदन में बताना चाहता हूं। सर, एक कहावत है कि झूठी बात कोई भी बोल सकता है, लेकिन सही बात बोलने के लिए, सही बात रखने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं अपने मन की बात रखना चाहता हूं। 2014 से जब से एनडीए की गर्वनमेंट आई है, तब से सिक्किम में चारों तरफ विकास हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी वहां पर एक एयरपोर्ट चल रहा है। 2018 में प्रधान मंत्री ने स्वयं आकर उसका उदघाटन किया है। उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं ही था, जिस टाइम माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला और मैंने याद भी दिलाया। दूसरा, सिक्किम को organic farming से जाना जाता है। इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि Central Government की तरफ से organic farming के लिए जितना हो सके, मदद करने से और अच्छा होगा। मैं यहां अपनी बात रखना चाहता हूं। विशेषकर सिक्किम में एयरपोर्ट को थोड़ा डेवलेप करना है। अपनी तरफ से मैं Central Government से गुजारिश करना चाहता हूं। विशेषकर National Highway - 10, जो Siliguri,

Sevoke to Rangpo तक अभी भी road connectivity नहीं है, कटा हुआ है। Siliguri, दो जगह से, बाहर से हो कर आना-जाना पड़ता है। National Highway हमारी लाइफलाइन है। इसलिए हम लोगों ने यह बात रखी है। हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सामने यह बात रखी है। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, यह काम पूरा करवा दीजिए। मैं सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि Sikkim देश का 22वां राज्य 1975 साल में हुआ है। 2025 में सिक्किम को 50 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इसमें विशेषकर सेंट्रल गर्वनमेंट की तरफ से भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा करते हैं और विशेषकर जो इस बार के सदन में सिक्किम की जो जटिल मांग है, जो issue है, उसको हमने स्पेशल मेन्शन के माध्यम से रखा है। अनस्टार्ड क्वेश्चन में भी आया हुआ है। जैसे organic farming के विषय में, ST status for Limbu-Tamang. उन लोगों को असेम्बली में सीट्स देने के बारे में है, 12 left-out communities का है, His Holiness Ogyen Trinley Dorje 17th Karmapa को सिक्किम लाना है। एयरपोर्ट का है। रोड का, NH-10 का है, विशेषकर Nathu La trade और कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में है। सर, कैलाश मानसरोवर का रूट सिक्किम से होकर जाता है। जैसे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तीन रास्ते हैं। पहला, नेपाल से होकर, दूसरा, उत्तराखंड से होकर और तीसरा सिक्किम से होकर जाता है। सिक्किम से by road कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जो सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। इसलिए कैलाश-मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाये, यह मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव रखना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता है कि जो बॉर्डर है, इधर अरुणाचल प्रदेश, लेह-लद्दाख से लेकर सिक्किम तक करीब-करीब 1,400 किलोमीटर है। हम लोग बोलते हैं चाइना बॉर्डर । यह चाइना बॉर्डर नहीं, यह तिब्बत बॉर्डर है, क्योंकि जितनी भी एलओसी है, इसमें चाइना नहीं है, इसमें तिब्बत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, जैसे आर्मी हुआ, बीआरओ, जीआरईएफ हुआ, इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये इसको चाइना बॉर्डर नहीं बोलें, बल्कि इसको तिब्बत बॉर्डर बोलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ तिब्बत बॉर्डर है।

दूसरी बात मैं इस सदन में रखना चाहता हूं कि जो एलओसी है, वहां पर चाइना की तरफ उन्होंने गांव बसाये हुए हैं, गांव बनाये हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाकर, उधर किसी को जाने नहीं देते हैं। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए मैं आपसे माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसकी तरफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर ध्यान दे। अंत में, जो बजट 2023-24 का रखा गया है, मैं इसका स्वागत करते हुए, अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद लेप्चा जी। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, शुरुआत करने से पहले, कल जब मैं वहां पर अपने फ्लोर लीडर के साथ बैठी थी, उपराष्ट्रपति जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वहां पर बैठने के लिए, I have to earn that space. तो मैं बस यही कहूंगी कि उनका

आशीर्वाद बना रहे। मैं जरूर आगे बढ़ूंगी, पर उड़ी बाबा कहकर नहीं बढ़ूंगी और फ्रंट बैंचेज़ पर नहीं आऊंगी।

सर, मैं दूसरी चीज़ यह कहूंगी कि निर्मला सीतारमण जी इस तरह का बजट बनाती रहें, तो शायद हम उस तरफ पाए जाएंगे। इस तरफ निर्मला सीतारमण जी पाई जाएंगी और अगला बजट क्रिटिसाइज करेंगी।

एक माननीय सदस्यः यह सपना है।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः सर, सपना हो, तो उसे हकीकत बनाना हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी ने अपना 7वां consecutive बजट दिया, तो उसके लिए मैं उनको congratulate करना चाहूंगी। साथ ही साथ, उन्होंने एक और इतिहास रचा है। उन्होंने प्रधान मंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत इस बजट को पेश किया है। यह प्रधान मंत्री सरकार बचाओ योजना तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र विरोधी यह बजट है और इसके कारण मैं इस बजट का समर्थन नहीं करती हूं। जैसे ही हमने इसे महाराष्ट्र विरोधी बजट बोला, हम पर आरोप लगने लग गए कि Vadhavan Port के लिए 76 थाउजेंड करोड़ का आवंटन हुआ है। सर, मेरे पास डिमांड फॉर ग्रांट्स है Ministry of Ports, Shipping and Waterways की, इसमें कहीं भी – ये लोग सब जो महाराष्ट्र के हित में बात करने की बात करते हैं, पर महाराष्ट्र विरोधी हैं, ये बता दें कि कहां पर इसका प्रोविजन किया गया है, कहां पर 76 थाउजेंड करोड़ का प्रोविजन इस बजट में हुआ है। यह भी असत्य महाराष्ट्र को परोसा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

सर, दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं महाराष्ट्र से आती हूं। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक राजधानी मुम्बई है। मुम्बई को बारे में भी कहा जाता है कि कोस्टल रोड दिया, यह दिया, वह दिया। सर, तीन महत्वपूर्ण एजेंसीज़ मुम्बई में हैं। उनमें से एक है बीएमसी, जिसका चुनाव दो साल से नहीं हुआ है। *

सर, मैं बीएमसी से शुरुआत करूंगी। वर्ष 2023 में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 6,080 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट का आकर उद्घाटन करते हैं। उसमें से एक भी प्रोजेक्ट आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। यह मैं 2023 की बात कर रही हूं। 2024 में फिर से 6,000 करोड़ का टेंडर आता है और उन कांट्रेक्टर्स को दे दिया जाता है, जो ब्लैक लिस्टेड हैं। ...(**व्यवधान**)...आप यह समझिए कि जो कॉरपोरेटर, बीएमसी और कांट्रेक्टर का नेक्सस है, वह इनके अंतर्गत फल-फूल रहा है। दूसरा, सर, मैं बताना चाहती हूं कि एक MSRDC है, कोई कोस्टल रोड की बात कर रहा था। सर, 2017 से जो North-Bound Coastal Road बन रहा है, वह आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 6,700 करोड़ का cost escalation हुआ है, दो कांट्रैक्टर बदल चुके हैं, पर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ...(**व्यवधान**)... हाँ, वहीं से होंगे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ गुजरात को ही जा रहा है।...(**व्यवधान**)...सर, एक सेकंड। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो फ्रंट बेंचर हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत एक्सपीरिएंस्ड एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि हाइवेज़ तो ऐसे बने हैं कि हम लोग

---

* Expunged as ordered by the Chair.

सर्राटे से चल देते हैं। सर, मुंबई-गोवा हाई वे एक नेशनल हाई वे है। सर, मैं आपको मुंबई-नासिक हाई वे और मुंबई-अहमदाबाद हाई वे की पिक्चर दिखा रही हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: पेपर मत दिखाइए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, ड्रोन कैमरा से पिक्चर ली है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, you cannot show the picture. आप जो भी आरोप लगाएं, वह कहें और यहाँ पर सब्सटेंशिएट कर दीजिएगा, पर इस तरह से पेपर मत दिखाइए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, हटा दिया है। ...(**व्यवधान**)...सर, उसमें मैग्निफाइंग ग्लास से हाई वे ढूँढ़ लीजिए - मैं इन्हें इसकी खुली चुनौती देती हूं।

महोदय, महाराष्ट्र को लेकर महाराष्ट्र के हित के खिलाफ यह जो करप्शन हो रहा है, मैं उसको सामने लाना चाहती थी। सर, Dharavi Redevelopment Project के अंतर्गत खुद उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी, जो पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं और हमारे पार्टी पक्षप्रमुख हैं, उन्होंने उस बात को उजागर किया है कि कैसे Dharavi Redevelopment Project के अंतर्गत भ्रष्टाचार हो रहा है और मुंबई की जो लेंड है, वह ली जा रही है।

सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर एक और चीज़ कहनी पड़ेगी कि बार-बार 76 हज़ार करोड़ का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो 4 लाख करोड़ की 17 इंडस्ट्रीज़ आने वाली थीं, वे महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात भेज दी गईं। जो महाराष्ट्र विरोधी काम हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा इनकी सरकार ने यह काम किया है। सर, 17 co-operative banks हैं। महोदय, ये co-operative banks इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो किसान हैं - यह जो बार-बार कहा गया है कि यवतमाल में किसानों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि वे जो लोन लेते हैं, वे co-operative banks से लेते हैं। 2023 में ही 17 co-operative banks बंद हो गए थे। सर, मैं बस wrap up ही कर रही हूं। मैं बस एक लास्ट चीज़ कह रही हूं, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र पर ही टिके रहना है, महाराष्ट्र को लेकर बहुत अनर्गल बयानबाजी हुई है। ...(**समय की घंटी**).. सर, last point यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कैसे Internship Programme शुरू किया है। महाराष्ट्र बजट में यह Internship Programme आया है। सर, 2014 में जो स्टेट का डेट था, वह 2.8 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन इनके आने के बाद 2024 में 9.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सर, महाराष्ट्र के साथ * करके, अपनी राजनीति के चलते ये एनाउंसमेंट्स की जी रही हैं। सर, मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगी।

उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करूंगी और इस बजट का पूरी तरह से विरोध करूंगी, क्योंकि यह महाराष्ट्र विरोधी बजट है, जय महाराष्ट्र।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: धन्यवाद, प्रियंका चतुर्वेदी जी। माननीय डा. सिकंदर कुमार, आप बोलिए।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: #

श्री उपसभापति: आप चूक गईं, यह रिकॉर्ड पर नहीं गया है। डा. सिकंदर कुमार, आप बोलिए।

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे 2024-25 के बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का सातवीं बार बजट पेश करने के लिए माननीया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में जहाँ एक ओर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर विकसित भारत का संकल्प दिखता है। महोदय, मैं छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते, हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूँ कि पिछले दस वर्ष में मोदी सरकार के कार्यकाल में इतनी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को मिली हैं, इन परियोजनाओं की वजह से हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं। चाहे मैं शिक्षा की बात करूँ, मेडिकल की बात करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि, बागवानी, एअर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, अकल्पनीय विकास हिमाचल प्रदेश में पिछले दस वर्षों में हुआ है और अगर वह हुआ है, तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, हिमाचलवासी कभी नहीं सोचते थे कि छोटे से प्रदेश को विश्वस्तरीय संस्थान, एम्स मिलेगा। मैं तो सदन के नेता और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय नड्डा जी का आभार वयक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने 1,500 करोड़ रुपये का एम्स हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रदेश को दिया। वह बहुत कम समय में तैयार हुआ और उसका लाभ हिमाचलवासियों के साथ-साथ हिमाचल के साथ जो प्रदेश हैं, वे लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं। महोदय, पिछले दस वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने जो परियोजनाएं दी हैं, मैं उनका जिक्र आपके माध्यम से करना चाहूँगा। जैसे, मैंने आपके साथ 1,500 करोड़ के एम्स का जिक्र किया। इसके अलावा, ऊना, हिमाचल प्रदेश को 450 करोड़ रुपये का पीजीआई सेटेलाइट सेंटर दिया। हमारे नालागढ़ में 350 करोड़ रुपये का मेडिकल डिवाइस पार्क दिया। हरोली, ऊना में 1,900 करोड़ रुपये का बल्क ड्रग पार्क दिया है। मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के लिए 206 करोड़ रुपये दिए हैं। मेडिकल कॉलेज चम्बा और नाहन के लिए 452 करोड़ रुपये दिए हैं। यह हेल्थ के सेक्टर में पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। दूसरी बात, इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी अटल टनल, जो एशिया की सबसे लंबी टनल है, उसके लिए 3,200 करोड़ रुपये दिए गए। वह टनल किसी ने बड़े कम समय में बनाकर दी, तो वह मोदी सरकार ने दी। मैं कल हमारे विपक्ष के मित्र को सुन रहा था। वे कह रहे थे कि रेलवे को कुछ नहीं दिया। जीएसटी से सब परेशान हैं। मैं तो हिमाचल की बात करता हूँ कि रेलवे के लिए केंद्र सरकार ने क्या दिया। अगर हम बजट बारीकी से पढ़ेंगे, तो अन्य प्रदेशों की बात तो इस बजट में

Not recorded.

पता लग जाएगी, लेकिन हिमाचल के लिए क्या दिया, वह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब पूरे देश में चार वंदे भारत ट्रेन चलीं, तो उनमें से एक ट्रेन सबसे पहले किसी प्रदेश को दी, तो आदरणीय मोदी जी ने वह हिमाचल प्रदेश को दी। इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मोदी सरकार ने किया। चंडीगढ़-बद्दी न्यू ब्रॉड गेज लाइन के लिए 1,672 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। ऊना-हमीरपुर न्यू ब्रॉडगेज लाइन के लिए 5,821 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। नंगल डैम-तलवाड़ा न्यू ब्रॉड गेज लाइन के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। कालका-शिमला हाईड्रोजन ट्रेन के लिए 870 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस यूनियन बजट 2024-25 में, 2,698 करोड़ रुपये का रेलवे बजट हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसके लिए मैं रेलवे मंत्री का भी और मोदी जी का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। महोदय, पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और आपदा के ऊपर हिमाचल प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार ने बहुत राजनीति की। पिछले वर्ष 1,782 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रदेश की सरकार को दिया। उस 1,782 करोड़ में से अभी भी unutilized fund पड़ा है और जो असल में बाढ़ प्रभावित थे, उन लोगों को वह सहायता नहीं पहुंची। आपदा के ऊपर राजनीति की गई, लेकिन इसके बावजूद 2024-25 के यूनियन बजट में इस आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री और मोदी सरकार को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़): कुछ पैसा नहीं दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः राजीव जी, प्लीज़ बैठिए।...(**व्यवधान**)... सिकंदर जी, आप बोलें ...(**व्यवधान**)...

डा. सिकंदर कुमारः मैं बजट पर भी आ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं बजट पर ही आ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बोलें ...(**व्यवधान**)... राजीव, जी बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

डा. सिकंदर कुमारः उपसभापति महोदय, reform, perform और transform के संकल्प के साथ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2021 और 2024 का वर्ष हम देखें, तो 8.2 प्रतिशत की विकास दर के साथ भारत आगे बढ़ा है और दुनिया की global growth में भारत का योगदान 15 प्रतिशत है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2028 तक global growth में भारत का योगदान 18 प्रतिशत होगा। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था आज पांचवे नम्बर पर खड़ी है, आने वाले समय में 2027 तक हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। इस संकल्प के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। जहां आज हमारी पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वहीं एक समय ऐसा भी था कि जब भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोन लेने के लिए गया था, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मना कर दिया गया, क्योंकि भारत के पास as a security foreign reserve नहीं था।

आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत जहां दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वहां दुनिया का चौथा ऐसा देश बना है, जिसके पास सबसे ज्यादा 655 बिलियन डॉलर foreign reserve है।

उपसभापति महोदय, आज हम वर्ल्ड की seven top economies की बात करें, तो seven top economies में अगर सबसे बढ़िया growing economy कोई है, तो हमारे देश भारत की है। आज हम seven top economies की cost of living देखें, तो दूसरे देशों की अपेक्षा अगर सबसे कम cost of living किसी देश की है, तो हमारे देश भारत की है। अगर सबसे कम cost of construction किसी देश का है, तो हमारे देश भारत का है। सबसे कम cost of energy किसी देश की है, तो हमारे देश भारत की है।

मैं बजट के बारे में कुछ आंकड़े आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में investment growth लगातार बढ़ रही है, banks credit growth लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जिस poverty, inflation, current account deficit, revenue deficit, Budget deficit की बात हमारे मित्र कर रहे थे, तो मैं भी कुछ आंकड़े सदन में रखना चाहता हूं। अगर poverty ratio की बात करें, तो 2013-14 में हमारे देश में poverty 29.17 परसेंट थी और 2022-23 में 29.17 से घटकर 11.28 परसेंट यानी कि poverty reduction in 10 years is 17.89 per cent. Now, people out of poverty index 24.82 करोड़, यानी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह आंकड़ा आईएमएफ का है।

उपसभापति महोदय, अगर मैं पिछले 10 साल के अपने एनडीए के कार्यकाल और 10 साल यूपीए के कार्यकाल का comparison कुछ डेटा के बेस पर करूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि inflation trend in the UPA Government 2010 से लेकर 2014 तक 9.4 परसेंट से 12.3 परसेंट था। Headline inflation year to year, अगर हम 2012-13 में देखें, तो 9.9 परसेंट और अगर हम 2021-22 में देखें, तो NDA की सरकार में हमारा headline inflation 5.5 परसेंट रहा। Capital expenditure as a percentage of total expenditure, यानी net interest payment in 2013-14 was 16 per cent and during NDA tenure, in 2023-24, it is 28 per cent. Current account balance as a percentage of GDP in 2012-13 was (-4.8) per cent and in 2021-22, it was (-1.2) per cent. Year to year real GDP growth in percentage terms during UPA tenure was 5.5 per cent and during NDA tenure, it was 9.1 per cent. Foreign Exchange Reserves as a percentage of GDP in 2012-13, it was 16 per cent and during 2021-22, it was 20.1 per cent. Exchange rate depreciation, जो रुपए का अवमूल्यन हुआ during UPA tenure, it was 6.3 per cent and during NDA time, it was 3.1 per cent. मैं Public Sector banks के ratios की बात करूँ, Net Interest Margin in 2013-14 was 2.45 per cent and in 2022-23, it was 2.72 per cent during NDA tenure. Return on assets was (0.5) per cent during UPA time and during NDA time, it is (0.79) per cent. Return on equity during UPA time it was 8.48 percent and during NDA time, it is 12.35 per cent. Current Account Deficit as a percentage of GDP in 2013-14 it was (-4.8) per cent and during NDA tenure, in 2023, it is (-2.0) per cent. Average monthly gross GST collection in 2018 it was 0.9 lac crore rupees and in June 2024, it was 1.74 lakh crore

rupees per month. Fiscal deficit as a percentage of GDP in 2009-10 was 6.7 per cent and in 2023-24, it is 5.6 per cent. Revenue deficit as a percentage of GDP in 2009-10 was 5.5 per cent and in 2023-24, it was 2.6 per cent. Cumulative FDI inflows during 2004-14 were 304.03 billion dollars. ...*(Time-bell rings.)*... Sir, I need two-three minutes.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD) *in the Chair.*]

During 2014-24, it is 628.31 billion dollars. Tax exemption during UPA time was two lakh rupees and during NDA time in 2024, it is 7.75 lakh rupees. Bank NPAs during 2014, it was 11 per cent and during 2024, it is (0.6) per cent. Infrastructure spending during 2009-14 was 1.54 lac crore rupees and during 2019-24 it is 44.3 lakh crore rupees. Wealth created during 2009-14 was 13 lakh crore rupees and during 2019-24 it is 320 lakh crore rupees. Forex addition during 2009-14 was 50 billion dollars and during 2019-24, it is 350 billion dollars. GDP rank in 2014 was 10th and during NDA tenure it is the 5th rank in the world. GDP during 2004-14 was 98 lakh crore rupees and during 2015-23 it was 159.7 lakh crore rupees. ...*(Time-bell rings.)*... Sir, I need two more minutes. Per capita income from 2004-2014 was Rs.86,454; during 2015-2023, it was Rs. 2.72 lakh. Tax payers during 2004-2014 were 3 crores 80 lacs; during 2015-2023, it was 6 crore 77 lacs. मैं कह सकता हूं कि मैंने जो इकोनामिक इंडिकेटर्स सदन में रखे हैं और मोदी सरकार ने जो आर्थिक नीतियाँ पिछले 10 वर्ष में देश में अपनायी हैं, उनसे भारत निश्चित रूप से आने वाले समय में तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनेगा और जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने लिया है, हम सब मिलकर विकसित राष्ट्र बनाने के इस संकल्प को पूरा करेंगे।

In the last, in my concluding remarks on the Union Budget 2024-25, I would like to once again congratulate to the Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, for its efficient fiscal management ...*(Time-bell rings)*... and presenting such a Budget which will really enhance the economic growth of the country and promote social welfare among each and every section of the society. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Next speaker is Shri Sandeep Kumar Pathak; time allotted is five minutes.

श्री संदीप कुमार पाठक (पंजाब): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। प्रधान मंत्री जी का कुछ समय पहले हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट्स बैठे हुए थे और वे जर्नलिस्ट्स प्रधान मंत्री जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि income inequality के बारे में आपका क्या मत है? प्रधान मंत्री जी थोड़े से मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि क्या सबको गरीब बना

दें? मेरा यह मानना है कि देश के प्रधान मंत्री जी को income inequality जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए था। सर, income inequality से health inequality होती है, education inequality होती है, social welfare inequality होती है, lifestyle inequality होती है, और overall देश में जो inequality आती है, वह income की inequality से ही आती है।

सर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जो 10 प्रतिशत लोग हैं, वे 80 प्रतिशत इनकम करते हैं और बचे हुए जो 90 प्रतिशत लोग हैं, वे बाकी की 20 प्रतिशत इनकम करते हैं, लेकिन जो 80 प्रतिशत कमाते हैं, उनसे टैक्स सिर्फ 20 प्रतिशत आता है और जो 20 कमाते हैं, उनसे 80 प्रतिशत टैक्स आता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको ज्यादा कमाने वाले अमीर लोगों के तरफ से टैक्स का contribution कम है और जो मिडिल क्लास है, उसकी तरफ से देश को चलाने के लिए 80 प्रतिशत टैक्स आता है। यह inequality की एक झलक है। यह ऐसी झलक है, जो किसी भी व्यक्ति को समझदार व्यक्ति को यह स्पष्ट कर देगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमारा देश विकासशील से विकसित कभी नहीं बन पाएगा।

सर, अगर आप देखें, तो कॉरपोरेट टैक्स 9 लाख करोड़ का है, इनकम टैक्स 11 लाख करोड़ का है और जीएसटी 10 लाख करोड़ का है। अगर आप 10 साल पहले का देखें, तो कॉरपोरेट टैक्स ज्यादा हुआ करता था, वह डबल होता था और इनकम टैक्स कम हुआ करता था, लेकिन आज इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। यह क्या बताता है? यह income inequality बताता है, unequal distribution of income बताता है और यह यही बता रहा है कि पूरे देश का भार, जो सैलेरीड और मिडिल क्लास है, वह अपनी पीठ पर लेकर चल रही है।

सर, अगर हम बड़े सिम्पल तरीके से इनको 3 कैटेगरीज़ में ले लें, तो एक अपर क्लास का सेगमेंट आ जाएगा, एक मिडिल क्लास आएगा और एक लोअर इनकम वालों की क्लास आ जाएगी, जिसमें फार्मर्स और मजदूर रहते हैं। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, तो 15 लाख से ऊपर की कमाई करने वालों को लगभग 30 प्रतिशत का इनकम टैक्स लगाते हैं। तो जो 15 लाख कमा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि 1 साल में अगर वे 15 लाख कमा रहे हैं, तो वे मिडिल क्लास से ही होंगे। आप 1 लाख के आसपास per month का अंदाजा ले लें, तो एक अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30 प्रतिशत देता है और अडाणी जी, अंबानी जी हों या कोई भी अमीर आदमी हो, वह भी 30 प्रतिशत का इनकम टैक्स देता है। इस प्रकार, यह बहुत ही contrasting difference है कि करोड़पति लोग भी 30 परसेंट दे रहा है और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30 परसेंट दे रहा है। सर, मिडिल क्लास के आदमी के जीवन में एक ही बदलाव आया है। पहले वह 9 बजे से 5 बजे तक काम करता था, आज 9 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक काम करता है, फिर वर्क फ्रॉम होम करता है, फिर सैटरडे और फिर संडे भी काम करता है। मिडिल क्लास ने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है, क्योंकि उसके सपने हैं। अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए वह काम कर रहा है, काम से कमाई कर रहा है और उस कमाई से टैक्स पे कर रहा है। आप उसकी इनकम पर उससे टैक्स लेते हैं और अगर वह कुछ खरीदता है, उस पर भी उससे टैक्स लेते हैं। अगर वह थोड़ा-बहुत इंवेस्टमेंट करता है, तो अब आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स और टैक्स के पैसे से ही हमारे वित्त मंत्री.... यह मैं हम सबके लिए कह रहा हूँ कि पेन-पेपर लेकर बैठ जाते हैं, मिडिल क्लास के पैसे में से चार पैसे इसकी टोपी, उसके सिर, उसकी टोपी, इसके सिर कर देते हैं। इस तरह से इसमें कोई विज़न नहीं है। मैं बहुत दुख के साथ

यह कह रहा हूँ। मेरे पास समय कम है, अगर आप मुझे समय दें, तो मैं बता सकता हूँ कि यह बजट किस तरह flop है। इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है।

ऑनरेबल सर, मिडल क्लास के लिए सबसे important चीज job है। आपने कहा कि 50 लाख जॉब्स देंगे और इसके तहत आपने कहा, जो बहुत interesting है कि जो एक लाख की सैलरी वाला जॉब देगा, उसको 3 हजार का incentive देंगे। आप मुझे यह बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो 3 हजार रुपए के incentive के लिए एक लाख का सैलरी देगा? कोई नहीं देगा। आप incentivise करके जॉब create नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जॉब क्रिएट करना है, तो आपको जो existing set-up है, agencies हैं, institutions हैं, companies हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा और नई कंपनीज़ बनानी पड़ेंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Twenty seconds are remaining. ...*(Interruptions)*...

श्री संदीप कुमार पाठक : सर, मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप मुझे दो मिनट का और समय दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Time is allotted by the hon. Chairman. ...*(Interruptions)*...

श्री संदीप कुमार पाठक: सर, अभी मोदी सरकार solar policy लेकर आई। आप इस पॉलिसी के तहत large-scale पर solar panels लगाने की बात कर रहे हैं।...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Your time is up Mr. Pathak. ...*(Interruptions)*...

श्री संदीप कुमार पाठक : सर, अडाणी ने इसमें 50 मिलियन का इंवेस्टमेंट किया है। क्या आपने दूसरी facilities या infrastructure तैयार किया है? आपने तैयार नहीं किया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): You have to complete within half a minute. ...*(Interruptions)*...

श्री संदीप कुमार पाठक : सर, कॉपर की कंपनी अडाणी जी के द्वारा लगाई गई है। आपने इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5 परसेंट से जीरो कर दी है, इससे उसको हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा, जो कॉपर के ingots लेकर आ रहे हैं। कॉपर पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 2.5 परसेंट से जीरो क्यों किया गया? यह किसको फायदा देने के लिए किया गया? ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री संदीप कुमार पाठक: सर, गुजरात में अडाणी ने एक कंपनी लगाई है, उसको इससे फायदा होगा। सर, आप फर्टिलाइजर में 13 परसेंट reduce कर देते हैं, कॉपर की इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो कर देते हैं - यह क्या है?

उपसभाध्यक्ष (डा. भागवत कराड़): संदीप जी, कृपया आप conclude कीजिए।

श्री संदीप कुमार पाठक: सर, विज़न कहाँ है? मेरा pain समझिए, मेरा दुख समझिए, विज़न कहाँ है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): See, time is allotted and it is as per the schedule. *...(Interruptions)...*

श्री संदीप कुमार पाठक: सर, दस साल पहले से बजट बनता आ रहा है, लेकिन आज भी बजट में कुछ नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): I am calling the next speaker. *...(Interruptions)...* You have to conclude. *...(Interruptions)...*

SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK: Thank you. सर, मेरा सिर्फ एक ही submission है कि इस देश में गरीब, गरीब होता जा रहा है, अमीर, अमीर होता जा रहा है और मिडल क्लास को लगता है कि वह अपना बोझ ढो रहा है। मिडल क्लास पूरे देश का बोझ ढो रहा है। सरकार को यह टैक्स-टैक्स खेलना बंद करके सही तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Next speaker is Shri K.R. Suresh Reddy.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, I would like to congratulate the hon. Finance Minister that for the first time in her seventh Budget, we could see a seal of belief for which she has been speaking so highly. पहली बार इस बजट में, in the initial pages itself, she has mentioned four castes. The castes she mentioned are; one, she spoke of the *gareeb;* two, she spoke of the *kisan;* three, she spoke of the women and; fourth, she spoke of the youth. Now, these constitute 99.99 per cent of the economic disparity, the economic divide, the difference between the haves and have-nots. So, I congratulate her that she has put a seal of belief in her seventh Budget for

the first time in the initial pages of her Budget speech stating very clearly that these four would be a priority. Then, as the statistics revealed in this august House of the growing disparity between the haves and the have-nots, the 1 per cent haves and the 90 per cent have-nots -- I would not get into those figures -- I would like to suggest to the hon. Finance Minister that, symbolically, जब बजट के समय हलवा बनता है, तो हलवा किसने बनाया, कितना बनाया, बात यह नहीं है, बल्कि बात यह है कि हलवा कैसे बाँटा गया। How have you distributed it? How will it be distributed? The confidence she has given us is that, yes, she has identified these four important castes and the entire House, probably, is unanimous on this issue that four of these castes should be targeted. Well, I wish her the very best but I would like to suggest कि आपने बात कह दी, अब पता नहीं क्या होने वाला है। So, let there be a quarterly, half-yearly inputs to this august House of how she is progressing in this. It is because earlier there was always एनडीए गवर्नमेंट की बदनामी हुई थी। यह No Data Available Government है, के नाम पर आपकी बदनामी हुई थी। So, at least, now, एनडीए का मतलब, इन चार मुद्दों पर No Delay Approach की तर्ज पर चलना चाहिए। सर, last four-five days से हाउस में बजट पर चर्चा हो रही है and the entire focus is talking about two States. उसमें कहा गया, A.P. Reorganization Bill and the other was the Bihar funding. As far as A.P. Reorganization Bill is concerned, I would like to enlighten this House a little bit of the genesis of the Telangana struggle. 60 साल का स्ट्रगल! 100 बच्चे शहीद हुए, कई बच्चों का years of graduation, years of study got disturbed and, eventually, when Telangana was achieved, it was achieved through two big struggles, one in 1969, जब पुलिस की गोलियां चलीं और one from 2001 to 2014 under KCR*ji's* leadership. It was one of the most peaceful movements, one of the most struggled movements and one of the most enlightened movements कि जब नौजवान बच्चों ने स्यूसाइड करते हुए तेलंगाना की मांग रखी और उसके बाद जब तेलंगाना बिल पास हुआ, तो I would say that it was a watershed moment in the history of Indian Parliament कि ultimately, the voice of the people have been heard. जब A.P. Reorganization Bill के through तेलंगाना का बिल पास हुआ, तो यहां से comments आए थे कि you have delivered the boy but killed the mother. आपने बच्चे को तो जन्म दिया, मगर मां, she expired. Sir, now, what I get to see in this Bill is something different. अगर आप मदर को benefit करना चाह रहे हैं, revive करना चाह रहे हैं, we have no objection. Mother here in this case is Andhra Pradesh. मगर बच्चे को आप सौतेली मां का प्रेम क्यों बता रहे हैं? Why a step-motherly treatment to the young growing boy which is Telangana? महोदय, जब भी कोई बिल पास होता है, you know very well, जब कोई बिल पास होता है, जब कोई बिल चर्चा के लिए आता है, उसके अंदर Objects and Reasons होते हैं कि यह बिल क्यों लाया जा रहा है, इस बिल का उद्देश्य क्या है। सर, जब आप A.P. Reorganization Bill के the Statement of Objects and Reasons को देखेंगे, I will take one minute to enlighten this House.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): The time is up. Please conclude.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, just give me some time. I just started. सर, हम लोग केवल चार मेम्बर्स हैं और आप केवल चार मिनट दे रहे हैं! ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Hon. Member, the Chairman, Sir, has allotted the time for five minutes. Please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, kindly bear with me because we are the only one.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please continue.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, just give me a couple of minutes. A couple of minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): One minute. One minute for you.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, we are four Members. Sir, the Objects and Reasons clearly says that the creation of separate State of Telangana for the betterment of social, economic and political aspirations of the people of that region has been a long demand. Pursuant to this, the Government of India in 2009 announced the process of Telangana. सर, टाइम नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तेलंगाना के लिए जब A.P. Reorganization Bill आया, आज उसके 11 साल हो गए, केसीआर जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कई बार ये demands भेजीं, जिनमें तीन-चार डिमांड्स हैं। आपने स्टील फैक्टरी रखने की बात कही थी, लेकिन आपने नहीं रखी है। आपने backward districts में funds देने के लिए कहा था, वह नहीं दिया। Most importantly, हमारे यहां 4,000 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट देने की बात थी, वह आपने नहीं दिया, and one of the most glaring, आपने कहा कि बिहार में floods आते हैं, इसलिए AIBP में - floods आते हैं, उसको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude. ...*(Time-bell rings.)*...

श्री के.आर. सुरेश रेड्डी : सर, जिस तरह वहां floods आते हैं, उसी तरह तेलंगाना में drought आता है। तेलंगाना का पानी नीचे है और जमीन ऊपर है, इसके लिए लिफ्ट इरिगेशन चाहिए और

कम से कम वह डिमांड AIBP में kindly consider कीजिए। ...(**व्यवधान**)... अब हम किसी और दिन बात करेंगे, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude. Please. I am calling the next speaker. Please Reddy*ji*. Now, the next speaker is Shri Mahendra Bhatt, ten minutes. Shri Mahendra Bhatt; not present. Next speaker is Shri Rwngwra Narzary.

श्री रवंगवरा नारजारी (असम): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के यूनियन बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं असम से हूं और United People's Party Liberal से हूं। मैं इस बजट का स्वागत करते हुए इसको सपोर्ट करता हूं।

Sir, I believe that any country's journey of development depends on capability of well-designed fiscal management. Budget is the lifeline of the country's development. India is a country of more than 140 crore of population and marvellously, the people of India have chosen NDA Government for the third consecutive term with a clear mandate to run the Government under the leadership of Shri Narendra Modi which is historic and rare in the world of political history.

I thank the honourable Finance Minister for her comprehensive people's development oriented, and of course, clear and powerful Budget presentation with the guarantee of India to occupy position of third largest economy in the world in the years ahead, which is a dream of Narendra Modi*ji* and the aspirations of the people of India, that is, *viksit Bharat*.

Taking into account the people's mandate and pursuit of *viksit Bharat*, this Budget focussing on four major castes, namely, poor, women, youth and farmers, is determined to realise nation's development.

The nine priorities envisaged in the Budget by the Finance Minister is the showcase of its clarity and vision for developed India and it visualizes comprehensive policy to generate robust scope for the benefits of all sections of the people. Focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class will take India on a further height of prosperity.

On this occasion, I would like to thank the hon. Prime Minister for taking holistic approach for enlisting the Assam's Charaideo Maidam in the UNESCO world heritage site. Thanks to the Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma for his untiring efforts for making Charaideo Maidam to receive the prestigious UNESCO tag.

Sir, the effort of the Government of India, to build up extensive economic and strategic relations with the nations of South-east Asia through 'Act East Policy", will boost up development opportunities for the North-Eastern States of India.

Sir, the budget for flood management in Assam is the most sought after and the need of the hour for the people of Assam. Flood has always been an enemy and a matter of great concern for the people of Assam every year. Assam has to combat flood with extra and unwanted burden amidst developmental works undertaken with State's Budget. The Brahmaputra valley and the Barak valley have always been the most-affected during the monsoon season. In the Brahmaputra valley, several transborder rivers like Sankosh, Aie, Manas, Beki, Pagladiya, etc., flowing down from Bhutan, have been causing unmanageable damage to the downstream area of Assam, particularly, in the Bodoland region. Therefore, Sir, at this juncture, I, on behalf of the people of Assam, warmly welcome the most sought after budgetary assistance for combating the flood, which will be a game-changer. Apart from flood assistance, a total of Rs.7,796.16 crores of budgetary outlay has been enhanced for the development of Assam and North-Eastern region. Some of the remarkable budget outlays are: Rs.1,000 crores for welfare of tea workers, especially, for women; increase in special package for Bodoland Territorial Council (BTC) from Rs.100 crore to Rs.174.66 crores; increase in the budgetary outlay for the development of Tea Board from Rs.135 crores to Rs.721.50 crores; 100 additional India Post Payments Bank branches to be opened in the North East; road infrastructure to be constructed through PMGSY; tribal areas of States to be bolstered under *Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan*.

Sir, in the railway sector also, the Government of India has undertaken remarkable projects for infrastructure development and connectivity of railway in the North-Eastern region. I want to highlight some glimpses of the initiative taken by the then UPA Government and the present NDA Government in the railway sector for the North-Eastern region. The annual average Budget outlay for Assam and North-Eastern region under UPA regime from 2009-14 was only Rs.2,122 crores, whereas under the NDA regime, till 2024, the Budget allocation has gone up to Rs.10,376 crores, which is five times than the UPA. With regard to construction of new tracks, during UPA, from 2009-14, it was only 67 kms, whereas, during NDA, during 2014-24, it has gone up to 173 kms. Apart from that, a total of 18 new projects involving construction of 1368 km railway track with Budgetary allocation of Rs.74,972 crores is undergoing in North-Eastern region. *...(Time-bell rings)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): You have to conclude. Your time to speak is over.

SHRI RWNGWRA NARZARY: Sixty stations will be developed as Amrit stations: Arunachal Pradesh, 1; Assam, 50; Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, 1 each and Tripura, 4.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Conclude please.

SHRI RWNGWRA NARZARY: Sir, I will take 30 seconds more. Sir, 470 rail flyovers and under-bridges have been constructed since 2014 by NDA Government. This will definitely bolster the economy of NER as well as expand the sign of love and affection towards the people of the North-Eastern region. *...(Time-bell rings)...* Therefore, Sir, I would say the budgetary outlays for Assam and North-Eastern region will definitely draw a new development altitude in the region.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Now, the next speaker is Shri V. Vijayendra Prasad; you have three minutes to speak.

SHRI V. VIJAYENDRA PRASAD (Nominated): Sir, I want to suggest something in the tax collection procedure where the Government can get an extra revenue of Rs.15,000 crores. I am a writer, Sir. When a producer gives me one crore rupees, what does he do? He deducts Rs. 10 lakhs as TDS, and with 18 per cent GST, gives me a cheque of one crore and eight lakh rupees. Now, I am supposed to pay these 18 lakh rupees to the Government in a month. So, when my Editor, at the end of the month, reminds me, I give a cheque to him and he presents it. Similarly, the producer who deducts Rs.10 lakhs as TDS is supposed to pay tax at the end of the quarter. So, the money that does not belong to me is with me for one month. And the money that does not belong to the producer is with me for one-and-a-half months. The GST collected by the Government every year is Rs. 20 lakh crores. So, when the Government collects GST for at least one month directly, the interest comes to around Rs.10,000 crores. There the TDS is with the producer for one-and-a-half months. On an average, the Government is getting rupees six lakh crores as TDS. That interest amount works out to nearly Rs. 5,000 crores. So, similarly, both of them, combined together, make Rs.15,000 crores just by making a small alteration in the system. The person, who is giving, directly pays the TDS to the Income Tax

Department and the GST Department. There is no paperwork at all. And, the Government will be saving around Rs.15,000 crores on interest. Thank you, Sir.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इतने दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। इस चर्चा में इस बार धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई, शिवजी भी आ गए, शिवजी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया और पद्मव्यूह भी आ गया, तो मैं इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सर, 9 जून को माननीय प्रधान मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की। माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां 9 सूत्री बजट प्रस्तुत किया। हमारे यहां नौ का बहुत बड़ा महत्व है। 9 सबसे बड़ा अंक है। खजाने में नव निधि होता है, नवरत्न होता है, नवधा भक्ति होती है, नवरात्र होते हैं, नौ तपा होते हैं और शरीर में 72 हजार नाड़ियां होती हैं, तो सात और दो का जोड़ भी नौ होता है। हृदय को रक्त प्रवाहित करने वाली 108 नाड़ियां हैं, उनका जोड़ भी नौ होता है और माला के मणिये भी 108 होते हैं, उनका जोड़ भी नौ होता है। यह जो नौ का शगुन है, इस शगुन के आधार पर बजट लेकर आए हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि माननीय मोरारजी देसाई जी ने छह बार बजट पेश किया और वे सौ साल तक जिए। अब निर्मला सीतारमण जी ने सात बार बजट पेश किया है, दो 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। यह इस नौ और सात का महत्व है।

महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। संसदीय लोकतंत्र की बात हुई। इस लोकतंत्र की बात में कहा गया कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी यहां सदन में बोल रहे थे, तो उनके बोलते समय हल्ला करके वॉकआउट किया गया। भारत की लोक सभा में उनका घोंट दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया।

5.00 P.M.

हमारे एक बहुत बड़े संत राघवाचार्य जी हैं। एक बार मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, गीता में एक शब्द आता है समाविष्ट कहे केशवः। हे केशव, समाविष्ट स्थितप्रज्ञ कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समय आने पर बताऊंगा, तो जिस दिन लोक सभा की कार्यवाही हुई और कांग्रेस ने हंगामा करके माननीय प्रधान मंत्री जी को बोलने नहीं दिया, उस समय दूसरे दिन सुबह राघवाचार्य जी का फोन आया कि घनश्याम क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि कुछ नहीं। प्रणाम महाराज। वे बोले तुम्हारे प्रश्न का जबाव देता हूं कि कल भारत की लोक सभा में जो हुआ, उससे पता लग गया कि स्थितप्रज्ञ कौन है, नरेन्द्र मोदी स्थितप्रज्ञ आदमी है, क्योंकि वे जो कुछ करते रहे हैं, निष्पक्ष भाव से जो कुछ करना है। वे ढाई घंटे तक भारत की संसद में बोलते रहे, इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से कहता हूं कि राजनीति मोदा जी के लिए कोई स्वार्थ का विषय नहीं है। उनकी राजनीति राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए वे समझे,"राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम" करके वे काम कर रहे हैं। कृपया, "जलते जीवन के प्रकाश में, अपना जीवन तिमिर हटाएं," नरेन्द्र मोदी की तपय ज्योति से एक-एक कर दीप जलाएं, यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां दो बहुत बड़ी बातें हुईं। पहली बात यह कि ये विकसित भारत की बात करते हैं। वर्तमान बजट में तीन बड़ी बातें हैं, जिनमें एक वर्तमान पर है, एक भूत के ठोस

धरातल पर है और एक भविष्य के चिंतन के साथ है। वर्तमान में तो इसलिए है कि जो 9 बिंदु हैं, उन पर कितना-कितना खर्च होगा, वह सब माननीय सदस्यों ने बताया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन 10 साल का जो ठोस धरातल है, जिसके ऊपर सब से बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार खड़ा है, सबसे अधिक एक्सपोर्ट, डिफेंस में प्रगति, वित्तीय कोष पर नियंत्रण, गरीब कल्याण योजनाएं और भारत की 7 परसेंट से बढ़ती हुई जीडीपी के आधार पर खड़ा हुआ है। भविष्य के चिंतन पर नीति आयोग की मीटिंग के आधार पर कहा गया कि जब तक भारत के प्रत्येक नागरिक की 1 लाख, 25 हज़ार रुपये महीने की आय नहीं होगी, और साल की आय कम से कम 15 लाख रुपये नहीं होगी, तब तक विकसित भारत नहीं होगा। उस प्रकार का भारत बनाने के लिए दृढ़ सोच के साथ आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह वर्तमान का भी बजट है, यह भूत का भी बजट है और भविष्य का भी बजट है। इस रूप में इस बजट को हमें देखना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि इस प्रांत को कुछ नहीं मिला, उस प्रांत को कुछ नहीं मिला। उसमें माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने राजस्थान का भी नाम लिया कि राजस्थान को भी कुछ नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, राजस्थान को क्या मिला, पाली, मारवाड़ और जोधपुर के पास में 30-30 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान को मिला है, वह 1,500 एकड़ का है। उसमें 40 हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान को मिला है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे, जो दिल्ली से मुम्बई का है, जो 1,200 करोड़ रुपये का है, वह सब राजस्थान को मिला है, और वह पूरा हो रहा है। इस सरकार के आने के बाद में माननीय गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री थे, उस समय राजस्थान की सरकार में और हरियाणा की सरकार में तथा भारत सरकार में, इनके प्रयत्न से समझौता हुआ और समझौता होने के पर गंगा, यमुना के पानी पर, जो 30 वर्ष से अटका हुआ था, वह पानी राजस्थान और हरियाणा को देना तय हुआ। उसके लिए ईआरसीपी के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए शेखावटी के और 4 जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमकाथाना के लिए, यमुना का पानी लाने के लिए 80 प्रतिशत पैसा भारत सरकार ने देना तय किया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान को मिला है। इसी प्रकार पिछले वर्ष से 8 हजार करोड़ रुपए ज्यादा राजस्थान सरकार को मिले हैं। यह इस प्रकार से, इस सरकार से राजस्थान के बजट में मिला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आई है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बार-बार कहते हैं कि हम जीत गए और बीजेपी हार गई? आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि बीजेपी हार गई। अगर बीजेपी हार गई, तो नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री की शपथ कैसे ली? यदि बीजेपी हार गई, तो निर्मला सीतारमण जी बजट क्यों पेश कर रही हैं? इस तरह से आप कहाँ से जीत गए?

महोदय, हमारे यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाती है कि दो पहलवान लड़ रहे थे। लड़ते-लड़ते एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया और धरती पर उसकी पीठ लग गई। रेफरी ने कहा कि यह जीत गया है, लेकिन नीचे वाले पहलवान ने कहा कि नहीं, यह नहीं जीता है, मैं जीता हूं। उन्होंने पूछा क्यों, तो वह बोला कि मैं आकाश की ओर देख रहा हूं और ये धरती की ओर देख रहे हैं। इस तरह से ये तो आकाश की ओर देखकर कह रहे हैं कि हम जीत

गए, जबकि चारों खाने चित्त हुए हैं। ये नॉर्थ-ईस्ट में हार गए, पश्चिम में हार गए, तमिलनाडु और केरल को छोड़कर दक्षिण में हार गए। ये सब जगह हार गए हैं, लेकिन दिल्ली में वैसा कह रहे थे। दिल्ली की सातों की सातों सीटें हार गए हैं, फिर भी आप वाले कहते हैं कि -- हमको दे रहे हैं उपदेश --कि आप हार जाओगे, ऐसा करो, वैसा करो। अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है कि कौन हारा और कौन जीता, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं हमारे यहाँ पर इस तरह की एक कहावत है।

महोदय, यहाँ पर दो बड़ी बातें कही गई हैं और उनमें से एक बात कृषि के बारे में कही गई है। कृषि के बारे में कहा गया है कि किसान आपके खिलाफ है, किसान के लिए आपने कुछ नहीं किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ समय पूर्व ले जाना चाहता हूं। महोदय, जब मैं बचपन में था, तभी से पोलिटिक्स में हूं और पढ़ता रहा हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। कांग्रेस पार्टी नागपुर अधिवेशन में - जब पं0 जवाहरलाल जी प्रधान मंत्री थे और आवड़ी के अधिवेशन में, एक प्रस्ताव लेकर आई थी कि भारत में कॉपरेटिव फार्मिंग लागू की जाए। वह प्रस्ताव पास करने की स्टेज तक पहुँच गया था। वह प्रस्ताव यह था कि सारी जमीनों पर से किसानों का मालिकाना हक समाप्त कर दो और किसानों का मालिकाना हक समाप्त करके सारे गाँव का एक कॉपरेटिव फार्म बन जाए। वे इस प्रकार से किसान का जमीन से अधिकार खत्म करना चाहते थे। .. (**व्यवधान**)..

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय भारत रत्न माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में खड़े होकर जबरदस्त खिलाफत की थी और महावीर त्यागी जी ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरु जी, जिन्होंने कॉपरेटिव फार्मिंग से किसान का जमीन पर मालिकाना हक समाप्त करने का कानून बनाया था, वे जो प्रस्ताव पास करा रहे थे, वह प्रस्ताव उन्हें वापस लेना पड़ा। अगर वह प्रस्ताव पास हो जाता, तो आज किसान के पास एक बीघा जमीन भी नहीं होती। इसलिए कांग्रेस तो शुरू से ही किसान के खिलाफ रही है। कांग्रेस का किसान से लेन-देन ही क्या रहा है? उन्होंने इसी प्रकार के काम किए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी किसान की चर्चा हो रही थी। यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के राज में कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। 15 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन हुआ था और कांग्रेस पार्टी को किसान विरोधी कहा गया था। ..(**व्यवधान**)..आप सुन लीजिए। ..(**व्यवधान**)..उन्होंने वह काम किया। ऐसा किसान के साथ एक बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ। मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन सी चीज़ है, जो बाज़ार में नीलाम होती है? क्या किसी फैक्टरी का प्रोडक्शन नीलाम होता है, कोई काम नीलाम होता है? ..(**व्यवधान**)..केवल मात्र किसान की उपज, जो उसे मजबूरी में लाकर नीलाम करनी पड़ती है। आज समय था कि इस प्रकार की खेती को लागू किया जाए।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

सभापति महोदय, आपने प्रमोद तिवारी जी से कहा था कि ये सर्टिफाइड फार्मर नहीं हैं। लेकिन मुझे आपने और सुरजेवाला जी, दोनों ने सर्टिफाइड फार्मर घोषित किया हुआ है।

श्री सभापति: मान्यवर, मैंने आपको आज से तीस साल पहले राजस्थान विधान सभा में भी सर्टिफाइड फार्मर घोषित किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: हाँ, किया था। मैं सर्टिफाइड फार्मर हूं और इसीलिए कहना चाहता हूं। . . ..(**व्यवधान**)..

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): सर, समय हो गया है। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने बजट पर दस मिनट में से तीन मिनट ही बोला है। उसमें भी इन्होंने कहा है कि राजस्थान को... राजस्थान के मुख्यमंत्री बिहार की तारीफ कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नीरज जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं कह रहा हूँ कि पंडित जी की एक खासियत है, आप कितना ही कर लो, ये किसी चक्रव्यूह में नहीं फसेंगे, न किसान को चक्रव्यूह में फंसने देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं, नहीं, किसान को भी नहीं फंसने देंगे।

संस्कृति मंत्री; **तथा पर्यटन मंत्री** (**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत**): आपको अपनों से ही मिलने की फुर्सत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जब किसान की बात करते हैं... अभी कह रहे थे कि यह जातीय जनगणना करो, तो मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि अभी-अभी जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया नई लोक सभा के बाद भाषण देने के लिए आए थे, जयराम जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आगे-आगे तो चल रही थीं महामहिम राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु जी, जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं। उनके पीछे चल रहे थे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, जगदीप धनखड़ जी, जो ओबीसी से हैं। उनके पीछे चल रहे थे माननीय प्रधान मंत्री जी, वे ओबीसी से हैं और मैं बेचारा गरीब ब्राह्मण इनकी आरती उतार रहा हूँ। मुझे यह बताइए कि आप इससे ज्यादा और हमारा क्या करना चाहते हैं? मैं काँग्रेस से कहता हूँ कि इससे ज्यादा वे और हमारा क्या करना चाहते थे? ...(**व्यवधान**)... फिर हलवे पर आ गए कि हलवा बनाया, तो वहाँ पर जो ऑफिसर थे, उनकी फोटो दिखा रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूँ जो हलवा खाने वाले लोग थे, वे आज के दिन तो यूपीएससी से सिलेक्शन लेकर सेक्रेटरी नहीं बने। वे जिस समय यूपीएससी से सिलेक्ट हुए थे, उस समय सब जगह काँग्रेस का राज था।

श्री सभापति: एक सेकंड। प्रमोद जी कुछ बोलना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, मैं कहना चाहता हूँ कि... ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अच्छा मतलब यह है कि चक्रव्यूह शब्द कॉपीराइट हो गया है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सर, चक्रव्यूह देखने की चीज़ होती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी... ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी, वह कहा गया है न कि इतने हिस्सों में बंट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ आया नहीं। अपने को उस गज़ल से ही कुछ सीखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप कुछ कहना चाहती हैं? ...(**व्यवधान**)... एक सेकंड।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ कि धनखड़ साहब कब से ओबीसी हो गए? धनकड़ साहब तो जाट हैं। ...(**व्यवधान**)... राजस्थान में जाट ओबीसी में हैं क्या? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सुनिए, सुनिए। ...(**व्यवधान**)... मैं सदन का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। कभी यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर कह रहा हूँ कि मैं जाट जाति से हूँ and I am proud to belong to this caste. यह जाति राजस्थान में ओबीसी में है और सेंट्रल स्टेज पर भी ओबीसी में है। ...(**व्यवधान**)... मैं जानता हूँ कि आपने रिश्तेदारी यही सोचकर की है। ...(**व्यवधान**)... आप तो जाटों से वाकिफ हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कर दूँ... ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पंडित जी, एक सेकंड। ...(**व्यवधान**)... डा. के. लक्ष्मण। बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Panditji, you will get time.

डा. के. लक्ष्मण (उत्तर प्रदेश): यह वाजपेयी जी के जमाने में ही पहली बार राजस्थान के जाट को ओबीसी सूची में शामिल किया गया। सेंट्रल लिस्ट में भी जाट ओबीसी है, क्योंकि काँग्रेस वालों को कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है, यह पता नहीं है। उनके नेता को भी ओबीसी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक बात और बताना चाहता हूँ। घनश्याम तिवाड़ी जी को पता होगा कि मैं जाट आरक्षण समिति से जुड़ा हुआ था। मैं उसका प्रमुख प्रवक्ता था और हमारी छः सदस्यीय कमिटी थी। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले और जो कहा, सो हो गया, पर जो यह दिल्ली से जारी हुआ, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जेसलमेर, बाडमेर में थे। वे ताबड़तोड़ हवाई जहाज से आए और इसे स्टेट लेवल पर कर दिया। राजस्थान वह प्रांत है, जहाँ जाटों को पहले सेंट्रल लेवल पर मिला, स्टेट में बाद में मिला। मैं तो उस पार्टी का सदस्य रहा हूं। तब आपकी पार्टी थी और मेरी पुरानी पार्टी थी। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात समझ गए न ...(**व्यवधान**)... और फिर सुनिए, उसमें भी कुछ कानूनी खामी रख दी, तो मुकदमा कई साल तक चलता रहा। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी: सर, आप वकील थे ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उस बारे में मैंने उच्च न्यायालय में वकालत की। नीरज जी, करनी पड़ी, पर चाहे कितनी कमी रख दो, किसान चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा, ऊपर वाले की कृपा है। पंडित जी ...(**व्यवधान**)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदय, मैं निवेदन ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पंडित जी, एक सेकंड। जयराम जी, खड़े होकर बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, पंडित जी को बोलते हुए चार मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं।

श्री सभापति: सिर्फ चार मिनट ही हुए हैं न, don't bother.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, हम बोलते हैं माराठों को भी ओबीसी में ले लो।

श्री सभापति: किन्हें?

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Marathas, in Maharashtra, Sir.

श्री सभापति: अच्छा। नीरज बोलो।

श्री नीरज डांगी: सर, बीजेपी तो पूरा ही एक चक्रव्यूह है, जिसमें ये सब फंसे हुए हैं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, यह गलत है। वहां तो कुछ और ही बात हो रही थी।

श्री नीरज डांगी: सर, आदरणीय गजेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि चक्रव्यूह तो समझने की चीज़ है, इसीलिए वे उसको समझ रहे हैं।

श्री सभापति: देखिए, एक छोटा सा सुझाव दूंगा और बिना फीस के। माननीय गजेन्द्र सिंह जी से उलझने से पहले सोच लेना। ठीक है, यह मैं सुझाव दे रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... पंडित जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय सभापति महोदय, मैं जब यह कह रहा था कि आरक्षण की जो बात चली, आप उस कमेटी में तो थे ही, पिलानिया जी उसके अध्यक्ष थे, बड़ा आंदोलन हुआ था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सीकर की सभा में आए थे। वह फोटो मेरे पास अभी भी है। वे बोल रहे थे और बोलते-बोलते मैंने वह कागज लेकर उनको पकड़ाया और उन्होंने कागज पढ़ा। इसलिए आपके आरक्षण में आपका योगदान तो है, लेकिन थोड़ी बहुत आहुति मेरी भी दी हुई है। इसलिए यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति: पंडित जी, आपने तो आखिर में पूर्ण आहुति दे दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: ठीक है। पूर्णाहुति करी।

श्री सभापति: हां, पूर्णाहुति।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह चक्रव्यूह है, ये 36 व्यूह होते हैं। चक्रव्यूह की रचना करने वाले द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य जो रचना करते, वे चक्रव्यूह में नहीं फंसते हैं। ...(**व्यवधान**)... अब मैं तो द्रोणाचार्य का वंशज हूं, इसलिए मैं किसी प्रकार के चक्रव्यूह में नहीं फंसूंगा, लेकिन दूसरा नाम जो दिया है- पद्म व्यूह दिया है। पद्म व्यूह का उदाहरण है, पद्मपत्रमिवाम्भसा कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ के ऊपर रहता है। नरेन्द्र मोदी जी का जो यह पद्म है, यह राजनीति के दलदल में भी कमल के समान खिला हुआ है। यह पद्म व्यूह ही ऐसा है, जो व्यूह चक्रव्यूह को तोड़ेगा और जो लोग आज भारत को तोड़ने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग हैं, उन सबका पर्दा फास करके रहेगा। आपको मैं यह बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा चल रहा है। आप अपना तो संभालिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): सर, बजट ...(**व्यवधान**)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह बजट है। जो मैं बोल रहा हूं, समझ लो यही बजट है। ...(**व्यवधान**)... हां, यही बजट है। ...(**व्यवधान**)... मैं कह रहा था कि आप पार्टी हमको उपदेश दे रही है। भारत के इतिहास में पहली कोई पार्टी है, जो मुलजिम बनी है। प्रमोद जी, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, हम साथ-साथ जीतकर आए हैं। ...(**व्यवधान**)... तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो पास बैठते हैं, उनसे बचकर रहें, क्योंकि उन्होंने एक फार्मुला तय कर रखा है कि जो उनके साथ संस्थापक सदस्य थे, उन सबको एक-एक करके बाहर निकाल दिया। चाहे वे शांति भूषण थे, चाहे वे योगेन्द्र यादव थे या और भी थे और जो बच गए, तो उनको अंदर भेज दिया। बाकि एक-दो जमानत पर हैं। अब अगर आप पास बैठे, तो मुझे बहुत चिंता है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए कम से कम आप उनसे बचकर रहें।

सभापति महोदय, ये जो जाति गणना, जातिवाद की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतशाही पार्टियां हैं। डीएमके परिवार के सात लोग मेम्बर हैं। माननीय राम गोपाल जी यहाँ नहीं है, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बजट यही है, वे कह रहे हैं न। माननीय पंडित जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: राम गोपाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम का पूरा-पूरा वर्णन करके काम पूरा किया है। नाम है समाजवादी, मायने समाजवाद में और परिवार के ही पाँच आदमियों को चुन कर लोक सभा, राज्य सभा में बैठा दिया, तो समाज बाद में

और परिवार पहले, यह समाजवादी पार्टी का काम उन्होंने पूरा करके बता दिया। यह जो इंडी गठबंधन है, यह गठबंधन नहीं है, पारिवारिक, प्रजातांत्रिक, सामंतवादी पार्टियों का गठबंधन है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, वरिष्ठ भी हैं, मल्लिकार्जुन नाम है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम् शिवजी का नाम है। शिवजी एकमात्र ऐसे देवता हैं, जिनकी प्राण-प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती है, और देवताओं की नहीं होती। इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण-प्रतिष्ठा करा दी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, यह क्या हो रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पंडित जी, ...(**व्यवधान**)... माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी, round up. ...(Interruptions)... Nothing is going on record. ...(Interruptions)... Nothing is on record. ...(Interruptions)... Can any one of you speak? ...(Interruptions)... आप में से एक बोलिए। ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Let Pramod Tiwariji speak. ...(Interruptions)... No, you are intimidating your Deputy Leader. ...(Interruptions)... What is this? ...(Interruptions)... You are intimidating your Deputy Leader. ...(Interruptions)... I am giving him permission. ...(Interruptions)... I am giving him permission to speak, and you are intimidating him. ...(Interruptions).. What is this? ...(Interruptions)... No, I am so sorry. ...(Interruptions)... Please continue. ...(Interruptions)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदय, ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)... ये अभी एनईईटी की बात कर रहे थे। ...(**व्यवधान**)... एनईईटी की बात करते समय ये कह रहे थे कि यह राज्यों का विषय है। ...(**व्यवधान**)... यह 42वाँ संविधान संशोधन लाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का काम कांग्रेस और डीएमके पार्टी ने मिल कर किया और इसी कारण से यह स्थिति पैदा हो रही है। यह 42वाँ संविधान संशोधन किया। ये संविधान के रक्षक बन रहे हैं! हाँ, मैं संविधान सेनानी हूँ, आपात काल में, आपको ध्यान है कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मुझे पकड़ा गया, मारा गया, मारते हुए ले जाकर जेल में डाला गया। ...(**व्यवधान**)... ये कौन से संविधान ...(**व्यवधान**)... ये संविधान के # हैं। ...(**व्यवधान**)... ये संविधान के रक्षक नहीं हो सकते। ...(**व्यवधान**)... ये संविधान के #हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: # will not go on record. ...(Interruptions)...

Not recorded.

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय सभापति महोदय, ये अग्निवीर की बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)... भारत की सेनाओं में शेखावाटी के लोग ...

श्री सभापति: एक सेकंड। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला: सर, मुझे मौका दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं आपको भी मौका दूँगा, एक बार मैं इनको मौका दे दूँ। तिवारी जी, बोलिए, बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, माननीय एलओपी के लिए इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, या तो ये स्वयं वापस ले लें या आप कार्यवाही से निकाल दें, [#]

श्री सभापति : आप तो बिल्कुल ही खोल रहे हैं। Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... This is expunged. ...*(Interruptions)*... I will look into it. ..*(Interruptions)*... I will look into it. This is expunged. ...*(Interruptions)*... I will look into it. ...*(Interruptions)*... नंबर एक, इसमें कोई विवाद नहीं है, ...(**व्यवधान**)... सुनिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, माननीय मल्लिकार्जुन खरगे जी अत्यंत सम्मानित हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खरगे जी को पाँच दशक से ज्यादा का अनुभव है और इस हाउस का सौभाग्य है कि देश की दो प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष, एक सदन के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता हैं। दोनों बहुत शालीनता में विश्वास करते हैं और दोनों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। Panditji, round up. ...*(Interruptions)*... I will look into it. ...*(Interruptions)*...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पंडित जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की बात करने वाले आपात काल को याद कर लें। ...(**व्यवधान**)... ये संविधान की बात करने वाले लोग 42वें संशोधन की बात कर लें और अग्निवीर की बात करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस इलाके से आता हूँ, कारगिल की लड़ाई में 100 से ज्यादा शेखावाटी के लोग शहीद हुए थे। वहां के लोग आज सेना में 1,20,000 अग्निवीर भर्ती हैं। 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिजर्वेशन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक भी राज्य में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया है। इसलिए अग्निवीर की स्कीम सेना के मजबूत करने के लिए है, सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए है और नवयुवकों को जीवनदान देने के लिए है। इन्होंने किसानों के बारे में, संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में जितनी बातें

[#] Not recorded.

कही हैं, वे सारी बेमानी बातें हैं। यह जो बजट है, यह भविष्य का भी बजट है, वर्तमान का भी बजट है और भूत का भी बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. *...(Interruptions)...* Sit down. One second. *...(Interruptions)...*

श्री राजीव शुक्ला: सर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि..

MR. CHAIRMAN: Rajeevji, let the temperature be down, and briefly.

श्री राजीव शुक्ला: सर, मैं एक मिनट के लिए उनकी बात मान लेता हूँ। #

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Shri Mahendra Bhatt. *...(Interruptions)...*

श्री राजीव शुक्ला: #

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Shri Mahendra Bhatt.

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीया वित्त मंत्री जी के इस बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, बजट को पूरा सुनने के बाद मैं यह बात दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि 2047 के लिए जो सपना देश के नागरिकों ने देखा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ेगा, उस दिशा में यह बजट सार्थक सिद्ध होगा। अगर मैं वैश्विक संदर्भ में भी कहूँ, तो मुद्रास्फीति की दर स्थिर है और इस दर को जो 4 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है, यह इस बात को प्रमाणित करता है।

महोदय, पहली बार इस बजट में देखने को मिला कि अब जाति आधारित बजट नहीं रहा। देश के प्रधान मंत्री जी ने एक नया संदेश पूरे विश्व को दिया है कि अब भारतवर्ष के अंदर चार जातियां होंगी, जिनमें गरीब, युवा, महिला और किसान होंगे। मैं अगर कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने इन जातियों के संवर्धन के लिए, इन जातियों के विकास के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, वे पूरे देश के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक)** *पीठासीन हुईं।*]

Not recorded.

महोदया, गरीब केवल बोला जाता था, लेकिन गरीबी को समझने का जो भाव समाज के बीच में होना चाहिए, गरीब के हित के बारे में जो केन्द्र की सरकार से, राज्य की सरकारों से अपेक्षा की जाती थी, उसका पिछले - अब तो मैं कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी का 11 साल का कार्य का प्रारंभ हो गया है, इन 11 वर्षों में उस गरीब की चिंता करने का जो सार्थक प्रयास प्रधान मंत्री जी ने किया है, वह आज भारत का एक-एक नागरिक समझता है।

गरीब कल्याण अन्न योजना - महोदया, मैं इसकी बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब कोरोना काल था, उस काल के दौरान किसी गरीब का चूल्हा नहीं जले, तो कोई भूखा नहीं सोवे, इस भाव के साथ और गरीब से गरीब व्यक्ति के घर के अंदर भी भुखमरी नहीं हो, इस भाव के साथ देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना आई। यह भी गरीब व्यक्तियों के लिए, जैसे नाई है, मोची है या जो बहुत छोटे कारोबारी हैं, उनके हित के लिए यह विश्वकर्मा योजना लागू की गई। इसके साथ ही, प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन - इन सब प्रकार की योजनाएं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ उन गरीब व्यक्तियों को मिला, जिनका आंकड़ा सरकार के पास है। मैं कह सकता हूं कि गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं इन वर्षों में और बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से गरीबी रेखा के बारे में जो बात थी कि गरीबी रेखा से कैसे गरीब व्यक्ति को आगे निकाला जा सकता है, गरीब की गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, उसके सारे कार्यक्रम सिद्ध होंगे। महोदय, दूसरी जाति महिला की है। भारत वर्ष की आधी आबादी बहनों की है, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए भी पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने सोचा है और मैं तो कह सकता हूँ कि भविष्य में जब इस सदन के अंदर 33 प्रतिशत बहनें आएंगी, तो इस सार्थकता को और बल मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, 'प्रधान मंत्री आवास योजना' में यह पहली बार हुआ है, पहले मकान होता था, उस मकान पर पत्नी का कितना अधिकार है, इसका कोई संबंध नहीं होता था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज बहनों के नाम पर आवास मिल रहे हैं और वे लखपति बहनें बन रही हैं। इस बार महिला स्वरोजगार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज मातृ शक्ति ने देश के हर कोने में स्थान प्राप्त किया है, चाहे वह सेना के क्षेत्र में हो, चाहे पैरामेडिकल के क्षेत्र में हो, हर दिशा में बहनों को स्वरोजगार या रोजगार के लिए संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं और इससे उनको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह प्रधान मंत्री मोदी जी का बड़ा कंसेप्ट है, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने लखपति दीदी की चर्चा की है। लखपति दीदी का कंसेप्ट इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहनों के नाम पर न संपत्ति होती थी, न स्थान होता था। अगर आज सरकार ने इस दिशा में पहल की है, तो मैं कह सकता हूँ कि देश की मातृ शक्ति ने प्रधान मंत्री के प्रति स्नेह दिखाया है और यही कारण है कि इस बार भी, अगर मैं उत्तराखंड की दृष्टिकोण से कहूँ, तो मातृ शक्ति का बहुत समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला है और हम पाँचों कमल प्रधान मंत्री को समर्पित कर पाए हैं। महिला समूह को शून्य प्रतिशत की दर पर ऋण की व्यवस्था भी अनेक राज्यों ने की है, जिनमें मेरे राज्य का भी एक स्थान है।

महोदय, मैं युवा शक्ति की बात करूं, तो युवाओं की दृष्टि से भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन के बहुत ज्यादा अवसर प्रधान मंत्री जी ने इसमें दिए हैं। जैसे इसी बजट में प्रथम बार

नियुक्ति पाने वाले युवाओं के वेतन के प्रत्यक्ष लाभ के तौर पर 15,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंदर पात्रता सीमा एक लाख मासिक है और 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत बजट के अंदर कौशल प्रशिक्षण के विषय भी रखे गए हैं। जहाँ तक शिक्षा ऋण का विषय है, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे प्रतिभावान छात्र होते हैं, जिनको उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक आवश्यकता रहती है, उस दिशा में भी यह बड़ा काम आएगा।

महोदय, चूँकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज देश के प्रधान मंत्री जी ने इसको बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। देश के अनेक क्षेत्रों में भारत के प्रति जो यह भाव रहता था कि भारतवर्ष के अंदर भारत में अनादि काल से धर्म स्थलों की गाथाएं विश्व में भारत के आध्यात्म के स्वरूप को बताती रही हैं। उस दिशा की ओर इस बजट में बहुत प्रावधान किए गए हैं। जब मैं विदेशी पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से कहूँ, तो इस बार 92.4 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं, जो पिछली बार से 51.7 लाख अधिक है। इसी प्रकार से पर्यटन वीज़ा के अनेकों अलग-अलग वीज़ा हैं, जैसे ई-पर्यटक वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-कॉफ्रेंस वीज़ा, ई-आयुष वीज़ा, ई-वधू प्रवेश वीज़ा, आदि। मैं कहता हूँ कि जो अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा है, जिसके तहत 24x7 टोल फ्री बहुभाषी व्यवस्था है, उसके कारण भी भारत अनेक विदेशी पर्यटकों के आने का एक स्थान बना है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी का प्रयास है कि लोग विदेश के बजाय भारतीय दर्शन को महत्व दें और उस दिशा में पिछले दिनों बहुत काम हुए हैं। महोदय, चाहे बिहार के अंदर गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया मंदिर का कॉरिडोर बनना हो, चाहे राजगीर में हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिर तथा नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना हो, चाहे ओडिशा के अनेकों दर्शनीय स्थलों, प्राचीन सुमित तत्व को श्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना हो, उस दिशा में काम हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस उत्तराखंड राज्य के अंदर चारों धामों में, जहाँ पाँच प्रयाग, पाँच बद्री का स्थल है, उन सभी स्थलों को विकसित करने में प्रधान मंत्री जी का योगदान रहा है। केदारनाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन 233 करोड़ रुपए की लागत से आज भव्यतम केदारपुरी स्थापित हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देश के अंदर पर्यटकों के माध्यम से भी किस प्रकार से देश के पर्यटन के स्वरूप को बढ़ा सकते हैं और उसको आर्थिक क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जिस प्रकार से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे वहाँ के स्थानीय कारोबारियों, व्यावसायियों को निश्चित रूप से लाभ मिला है।

प्रधान मंत्री जी के काजीरंगा में एक रात रुकने के बाद वहाँ पर देश और विदेश के पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने के बाद वहाँ भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उनके द्वारा द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा के बाद, गहरे समुद्र के अंदर द्वारका नगर के दर्शन के लिए डाइविंग की तस्वीर जारी करने के बाद वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उनके लक्षद्वीप के बीच पर टहलते हुए और स्काई डाइविंग की फोटो और विडियो ने लक्षद्वीप को पर्यटन का केंद्र बनाया है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 130 मिलियन पर्यटक वहां घूमने आ चुके हैं, जबकि पहले 7 मिलियन पर्यटक ही वहां पहुंचते थे। मैं कह सकता हूँ कि इससे लगभग 65 प्रतिशत पर्यटन व्यवसायों को लाभ हुआ है। उनके द्वारा बैद्यनाथ मंदिर, झारखंड के लिए देवघर में हवाई

अड्डे का उद्घाटन किया गया, उज्जैन में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बनी। हिमाचल की जाखू पहाड़ी पर हनुमान जी की प्रतिमा बनी, रामेश्वरम एवं पश्चिमी बंगाल में भी भविष्य में हनुमान जी की बड़ी प्रतिमाएं लगेंगी। मैडम, मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के बारे में विश्व के अंदर यहां के आराध्यों, यहां के धर्म स्थलों और यहां की सांस्कृतिक विरासतों के प्रति जो भाव है, अगर मैं यह कहूँ कि आज भारत ने पूरे विश्व के अंदर इस दिशा में एक अलग पहचान बनाई है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, Statue of Equality की स्थापना की गई है। इन सब के कारण इन सभी शहरों की इकोनॉमी बढ़ी है और कुछ स्थानों में 23 प्रतिशत तक का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है।

कश्मीर घाटी में 1,842 पर्यटक स्थल हैं, जिनमें से 952 मंदिर हैं और उनमें से 212 में आज भी पूजा होती है और इस बीच 740 के सुधारीकरण का काम हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर जो स्वरूप बना है, उससे हम सब लोग वाकिफ हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम आज के विश्व पटल पर कश्मीर को देखते हैं, आज हम अपने भारतवर्ष के दृष्टिकोण से कश्मीर को देखते हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर, जो कि हमारे भारत का मुकुट था, उस मुकुट में पुनः चार चांद लगने का काम हुआ है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री महेंद्र भट्टः मैडम, मैं अब खत्म कर रहा हूँ। 5 नवंबर, 2021 को केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ है। वहां 2017 में आपदा आई, जिसकी चर्चा मैंने कर दी है। राम पथ गमन मार्ग - 9 राज्यों को मिलाकर बनने वाली इस परियोजना से 15 प्रमुख स्थानों पर लाभ मिलेगा। विश्व के अंदर भी भारत के मंदिरों की स्थापना का एक नया कार्य प्रारंभ हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि आज विश्व के अंदर भी भारत के आराध्यों के प्रति मान-सम्मान बढ़ा है। 2018 में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई और 2019 में भगवान कृष्ण का मंदिर भी वहां पर बना है।

महोदया, मैं कह सकता हूँ कि चूंकि मैं पर्यटन क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैंने इन सारे विषयों की जानकारी दी है। इन सब बातों से पूरे विश्व के अंदर निश्चित रूप से भारत की एक छवि बनी है, भारत के आध्यात्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ...(**समय की घंटी**)... योग शिक्षा की दृष्टि से भी आज ऋषिकेश जैसे स्थान पर जिस प्रकार देश-विदेश के लोग आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि भारत की यह धरोहर है और इस धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए मोदी जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shri Haris Beeran. You have five minutes.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the Discussion on the Budget of 2024-25. First of all, I have to painfully remind the Finance Minister that there still exists a State, called Kerala. There is a new term which has been evolved, which is called a *'double engine sarkar'*. Every sop has been given to these '*double engine sarkars*'. Previously, it was given to BJP *sarkars*. Now, it is given to the allies also because the engine is being pulled and pushed by the allies. I don't have any qualms about giving funds to other States, but just see the contrast. What did my State, Kerala, ask for? Kerala asked for Rs.24,000 crores as a package for two years; Rs.5,000 crores for an International Trans-shipment Container Terminal in Trivandrum; and Rs.5,580 crores for the National Highways. They asked for establishment of AIIMS, but no AIIMS has been given, although 26 AIIMS have been established up till now. Nothing has been provided for the rubber farmers, or, for the coconut farmers.

As far as fishermen are concerned, this is the rainy season over there. It is a long coastal stretch. There is huge coastal erosion. Sea erosion is happening. Their homes are under huge threat. Nothing has been provided for them.

Madam, you know what has happened in Wayanad today. The entire House was there in session asking as to what is happening in Wayanad. It is a disaster of unprecedented magnitude. As far as giving of Disaster Management Funds is concerned, only five States are favoured by the Finance Minister. I request that during her reply, the Finance Minister allocates funds towards Disaster Management Fund for Wayanad and Kerala also. I demand that she allocates fund for construction of sea walls for the fishermen folks who are living in the coastal regions. Madam, contrast to this with what she gave to the two States, Bihar and Andhra Pradesh -- special projects, special status to the States and everything. So, what does this mean? It means that you are actually conveying to the world that you are at gunpoint before your allies. You are telling the world that you are not a stable Government. You want foreign investment to come to the country. For that, what do you need? You need social fabric or climate of the country to be in good spirit. But, what is happening here? Complete divisiveness is happening in this country. The other day, what happened in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh? It was some kind of a racial profiling, which had happened in South Africa long time ago. There was one great man, who was actually against that racial profiling, and, his name was Mohandas Karamchand Gandhi, and, all this is happening in the country of Gandhi in 2024! And, you want foreign investment to come to the country! You say, *'Sabka Saath, Sabka Vikas'*. Then, why certain communities are targeted, why their livelihood is affected, and, why their homes are bulldozed. You have a Ministry of Minority Affairs

and the total extent of Budget allocation is 0.07 per cent. The allocation for education and empowerment of minorities was Rs. 1,689 crores, which has been reduced to Rs. 1,500 crores. Scholarship for students under Maulana Azad Foundation has been scrapped. Maulana Azad Fellowship has been reduced from 96 to 45 crores of rupees. I demand restoration of all this. This particular ministry is for upliftment of the marginalised communities but it is marginalising the marginalised communities.

As far as Census is concerned, there is no word in the Budget Speech about Census, there is no allocation for the Census. Census has not happened for the last three years. There is no explanation as to why Census has not happened. As far as NRIs are concerned, you milk them in whatever possible way you can. The airfares are exorbitantly high. You don't give them the voting rights. Similar is the case with migrants. There is no welfare for the migrants. There is no voting rights for the migrants.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: I am concluding with one Constitutional issue. Madam, Article 112 of the Constitution deals with the Budgetary provisions. Let me read one sentence. The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year." What has happened in the Budget speech? *(Time-bell rings)* But in paragraph 35, it is mentioned, "An additional allocation will be provided this year towards capital investment." This is not allowed under the Constitution.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: I am concluding in thirty seconds. This kind of a statement that additional allocation will be provided is completely unconstitutional. I demand that this particular sentence should be deleted from the Budget speech. Either it is a political speech or in the guise of this particular thing, she wants to allocate something else to the other States, which do not deserve that. This is totally unconstitutional. Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Dr. K. Laxman. You have ten minutes.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Madam, at the outset, I would like to congratulate the Modi Government. This is the thirteenth time the Budget is being presented by this Government after Narendra Modi's Government has come to power for the third term, which is again a history. 60 साल के बाद एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति, जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची - लोकतंत्र के माध्यम से तीसरी बार प्रधान मंत्री बना - यह मोदी जी से संभव हुआ। 60 साल के बाद एक इतिहास रचा गया है। I would like to congratulate our hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman *ji*, for presenting the Budget for the seventh consecutive time. It is also again a record. This Budget is a roadmap for 2047 for making this country a *viksit bharat*. विकसित भारत का मतलब - मोदी जी ने जो संकल्प लिया, वह सभी राज्यों के हित के लिए सोचने वाली सरकार, सभी राज्यों के हित के लिए काम करने वाली सरकार है, इसलिए विकसित भारत माना जाता है। मैं सात दिन से कई नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। As far as my knowledge goes, the Union Budget is an annual financial statement which outlines the Government's revenue and expenditure for the upcoming financial year. I am neither an economist nor a financial adviser. I am a layman when it comes to the figures of the Budget. But I would like to make it very clear. हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे जी बोल रहे थे कि यह बजट सिर्फ दो ही राज्यों के लिए रखा गया है। एक राज्य को पकौड़ा और एक राज्य को जलेबी दी गई, ऐसा उन्होंने कहा। उसी दल के अंदर हमारे एक कांग्रेस के सांसद, जो बिहार से आते हैं, वे मल्लिकार्जुन खरगे जी की बात न मानते हुए बोलते हैं कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया। एक ही दल के अंदर किस तरह से लोगों को * करने के लिए यह double talk होती है। चुनाव में किस तरह भ्रम पैदा करके चुनाव जीतने की * की, इसी तरह बजट के बारे में भी आपके बिहार के नेता बोलते हैं कि बिहार को कुछ नहीं दिया और अब बोलते हैं कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट दिया गया है। हमारे अन्य सदस्य भी बार-बार यही जिक्र करते हैं। आंध्र-प्रदेश के नेता भी बोले कि आंध्र-प्रदेश को कुछ नहीं दिया। इससे साबित होता है कि बजट के बारे में हकीकत में सिर्फ राजनीति के माध्यम से बोलना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तेलंगाना से आता हूं। मुझे आपको बताते हुए ताज्जुब होता है, अभी चार दिन पहले वहां बजट सेशन किया जा रहा था। यहां यूनियन बजट पारित होने के बाद, वहां एक प्रस्ताव रखा गया कि यह यूनियन बजट पूरी तरह तेलंगाना के खिलाफ है। सिर्फ आंध्र-प्रदेश और बिहार के लिए रखा गया है। यह प्रस्ताव, वहां के दोनों दलों ने पारित किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि दूसरे दिन ही जो बजट पेश किया गया, उसमें वहां के मुख्य मंत्री बजट में बताते हैं कि तेलंगाना के लिए केन्द्र सरकार से लगभग 25,639.84 करोड़ रुपये share of Central tax के लिए मिले हैं, Grants-in-aid 21,075 करोड़ रुपये मिले। एक तरफ कहते हैं कि तेलंगाना के लिए कुछ नहीं दिया। Budget At a Glance is now being presented by the Finance Minister of that State showing that almost Rs. 70,000 crore has given to Telangana by the Modi Government. लोग बार-बार बता रहे हैं कि यूनियन

* Expunged as ordered by the Chair.

बजट के अंदर सभी राज्यों का नाम नहीं लिया गया। यह मुझे समझ में नहीं आता है। यूनियन बजट में इतने राज्यों का नाम लेना जरूरी नहीं है। मैं कांग्रेस के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि जब तेलंगाना के बजट में प्रस्ताव रखा गया, वहां पर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कितने जिलों का आपने नाम लिया, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। इस तरह राजनीति करना ठीक नहीं है। आप वहां बजट के अंदर एक-दो जिलों के नाम पर प्रस्ताव रखकर किस तरह बाकी जिलों को भूल गए, हमें पता है। वहां हैदराबाद, जो capital city है, 70 per cent of revenue comes from Hyderabad alone to the Telangana State. महोदया, मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं दो बार हैदराबाद से विधायक था। मैं पूछ सकता हूं वहां की कांग्रेस सरकार से कि हैदराबाद के लिए उसने बजट में क्या दिया है? मगर मैं मानता हूं, State Budget reflects the entire State. This is the Union Budget. It reflects the entire country. यह जानकारी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मगर हैदराबाद को क्या दिया, आप आंकड़े देखिए। आपके मुख्य मंत्री ने हैदराबाद को किस तरह * किया और हैदराबाद से कितना रेवेन्यु आता है, मगर मैं यह पूछना भी नहीं चाहता हूं। Approximately 70,000 crore rupees have been shown for Telangana, इस यूनियन बजट के नाम से। इतना ही नहीं आज infrastructure की बात होती है। Rs.11,11,000 crore is the record Budget given to the entire country for the development of roads, highways, railways, airports and even seaports. This is the development which we have been seeing for the last ten years. I would like to make it very clear what Modi ji's Government has given to Telangana for the last ten years. Nearly ten lakh crore rupees have been given to Telangana in the last ten years. National Highways के लिए सिर्फ तेलंगाना को ही एक लाख, 10 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए हैं। जब तेलंगाना नहीं बना था, उस समय combined आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना में कोई नेशनल हाईवे ही नहीं था। आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक आपके नेतृत्व में 2,500 किलोमीटर रोड बनाई गई, आप 60 साल तक सरकार में रहे, राज्य में भी थे और केंद्र में भी थे। मगर पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में तेलंगाना के अंदर 2,500 किलोमीटर रोड रिकॉर्ड स्तर पर बनाकर दी गई है। वहां निज़ामाबाद के अंदर, जो आरमूर के किसान हैं, हल्दी पैदा करने वाले किसान हैं, उनकी मांग थी कि एक turmeric board बनाया जाए। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए turmeric board बनाकर अपना वादा निभाया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 70 साल में आप तेलंगाना को एक एम्स भी नहीं दे सके। 70 साल में आपने एक एम्स भी नहीं दिया, आज पहली बार मोदी जी की सरकार ने तेलंगाना को एम्स दिया है। उसी तरह आपके ज़माने में *Ramagundam Fertilizers and Chemicals* फैक्ट्री थी, जो बंद की गई थी, जो किसान के हित के लिए उन्हें यूरिया व फर्टिलाइज़र सप्लाई करती थी, लेकिन मोदी जी की सरकार के आने के बाद 6,636 करोड़ रुपये का अलग से बजट देकर, फिर दोबारा *Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited* को चालू किया है। आज उसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा, आज पूरे दक्षिण भारत के किसानों को on demand यूरिया और फर्टिलाईज़र दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, 2,400 मेगावाट्स का एक पावर प्लांट, NTPC के प्लांट के लिए 11,000 हजार रुपये मोदी जी की सरकार ने आवंटित किए हैं। मगर वहां की राज्य

सरकार 4 लैटर्स यहां से लिखने के बावजूद भी, आज आगे नहीं आ रही है। उसका मतलब अलग है, वह अलग private agency से, वह अधिक रेट से पावर लेना चाहती है।

इसके अलावा पहली बार, 70 साल में ट्रायबल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी तेलंगाना में स्थापित की गई है। आदिवासी देवी-देवताओं के नाम पर, सम्मक्का साराक्का के नाम पर मोदी जी ने एक ट्रायबल यूनिवर्सिटी दी है। जयराम रमेश जी, आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार केन्द्र में भी थी और राज्य में भी थी। मगर आपने कभी भी आदिवासियों के हित के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दी। ...(व्यवधान)... आज Regional ring road के लिए 21 हजार दिया जा रहा है। इसके लिए भी हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार आगे आए। वारंगल में wagon manufacturing factory दी गई है। उसके अलावा रेलवे के लिए, I really thank our hon. Minister for Railways Ashwini *ji* for the record level budget that has been given to the two Telugu-speaking States. They are: Andhra Pradesh and Telangana. Earlier the highest allocation to the combined State of Andhra Pradesh was only..

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

DR. K. LAXMAN: Madam, my time is 15 minutes. It was Rs.884 crore only.Now Telangana alone has got Rs.5,336 crore and Andhra Pradesh has got Rs.9,151 crore. You can see how much the difference is. Hardly, they have given Rs.886 crore for the entire Andhra Pradesh combined State. Now, entire Telangana and Andhra Pradesh have become 100 per cent electrified. Apart from that, we have got four Vande Bharat trains for Andhra Pradesh and Telangana -- two trains from Secunderabad to Visakhapatnam, one train from Secunderabad to Tirupati and one train from Kacheguda to Bengaluru. Madam, devolution of taxes to Telangana during UPA was Rs.82,227 crore in 2004-05. But in Modiji's Government, in 2024-25, Telangana got Rs.12,19,782 crore as devolution of taxes. It is a record level tax which is being given to Telangana. Like that, even in the South India, we got Rs.58,487 crore during UPA term in 2013-14; now, we got Rs.1,97,059 crore. आप कांग्रेस के नेता मांगते हैं, वे दक्षिण के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप जो तोड़-फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, इसकी जानकारी आज दक्षिण के लोगों को भी हो गई है। उन्होंने आपको दक्षिण में किस तरह के ठुकराया है और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है - इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस - सात महीने पहले तेलंगाना में जो सरकार थी, 6 गारंटी के नाम पर and 66 assurances have been given but nothing has materialized.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

DR. K. LAXMAN: Yes, Madam. सौ दिन के अंदर आपने जिस गारंटी पर अमल करने का वादा किया था, आपने उससे किसानों को * दिया, युवाओं को * दिया, महिलाओं को * दिया। आज महिलाएं 8,500 रुपये के गारंटी कार्ड लेकर कांग्रेस के कार्यालय पर घूम रही हैं। खटाखट, खटाखट आओ और लो 8,500 रुपये। आपके नेता ने 1 लाख रुपये देने की बात की थी और लोग उनके चक्कर में फंस गए। महोदय, मैं लोक सभा की डिबेट सुन रहा था। आपके विपक्ष के नेता ओबीसी के बारे में, एस.सी. के बारे में, एस.टी. के बारे में जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जो बार-बार जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं ..(**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

डा. के. लक्ष्मण: मैं पूछना चाहता हूं कि 1931 के बाद से आपकी जितनी भी सरकारें थीं, आप कितने दशकों से सत्ता में थे - अंग्रेज़ों के जमाने में सेंसस हुआ, मगर आपके जमाने में कभी सेंसस नहीं हुआ। आप सिर्फ बार-बार, हमारे द्वारा जातिगत जनगणना कराने का जिक्र कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक के अंदर, जब आपकी सरकार थी, सिद्धारमैया जी मुख्य मंत्री थे, तब आपने जाति के नाम पर सर्वे कराया, मगर उसको प्रचलित नहीं किया, क्योंकि आपने अपनी अंदरूनी गड़बड़ी के कारण यह किया। महोदय, हमारी इसी एनडीए सरकार ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना का सर्वे कराया और आंकड़े भी प्रचलित किए।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

डा. के. लक्ष्मण: यह हमारा ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में विचार है।

महोदया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से केवल एक ही सजेशन फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि, The major issue for middle class is removal of indexation benefit. यह बजट पेश होने के बाद जब मैं हैदराबाद गया था, तो they came to me and expressed their desire to see that this amendment is made. There will be an extra tax burden. Hence, an option of indexation should be given to the middle class up to a certain amount. मैडम, इसीलिए जब मोदी जी की सरकार सबके हित के लिए सबका साथ-सबका विकास बोलती है, तो वह चाहती है कि वह विकास सामाजिक और भौगोलिक रूप से हो। महोदया, यह जो यूनियन बजट पेश किया गया है, मैं इसका स्वागत करते हुए आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, hon. Member, Shri Jose K. Mani; five minutes.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Madam, I thank you for giving me this opportunity. With a heavy heart, I am standing here. There was a report of the tragedy which took place in Wayanad where almost 70 persons have died and the toll is going up. We expected the House to pay homage and condolences to the families but it was not done.

Having said that, when I heard the Budget being read I can't help but remember the name of Chetan Bhagat's book -- 'Two States'. Is this a Central Budget or a Budget of two States? First time in the history of India, natural calamity and its management had taken a political colour. I am not talking about the incident which took place in Wayanad but what happened earlier. Madam, history has shown that appeasement of regional interest can harm the nation. Several parties with regional importance had left the rulers who had given more funds and joined the opposite forces. Take a view of it. Assess if your AB strategy is correct.

6.00 P.M.

So, this is not *'Sabka Saath, Sabka Vikas'*. This is सिर्फ दोनों के साथ, दोनों का विकास। People want to ask a plethora of questions to the Centre regarding this Budget. Kerala model of development is a model not only for Kerala, not only for the nation but also for the whole world. The human development indicators are comparable to the Scandinavian countries. Madam, the 2018 and the 2019 floods severely impacted us causing huge losses to the State. Subsequently, every year, we are suffering natural calamities including, especially, the floods that happened today. Did the Government give sufficient compensation and relief? The answer is 'No' and thus it is unfair to Kerala. *...(Interruptions)...* Kerala has the best cash crops, especially, spices like cardamom and pepper. It has brought huge foreign exchange. Does the Government address their genuine concern? Again, the answer is 'No'. Here again, the Centre was unfair to Kerala. Kerala has been talking about rubber. Even me, when I was in the Lok Sabha, for ten years, invariably, I was asking for the problems of rubber farmers and outside the Parliament also. Again, we know that there is a high demand for rubber. Last year alone, five lakh tonnes of rubber has been imported. See, what the Government did. They changed the policy in favour of the corporate companies. Again, the Centre was unfair to Kerala. Kerala's health sector is widely regarded as the best in the country. Kerala's nurses are highly sought after worldwide. Still, our longstanding demand for an AIIMS was rejected. Again, the Centre was unfair to Kerala. My questions can go on and on but due to paucity of time, I am limiting here. Madam, why this step motherly attitude towards Kerala? Even Satyawati, who was

step mother of Bheeshma and great grandmother to Pandavas and Kauravas, was never partial. Then, why neglect Kerala? The real answer is that the BJP in Kerala does not anticipate any political gain at all even in the future. The Budget talks about four sectors, the poor, the youth, the women and also the farmers. However, there are no concrete proposal schemes for the upliftment of these sections. The Finance Minister has mentioned the word 'poor' just once in her Budget speech. This shows how concerned the Government is towards the cause of downtrodden. The poor have become poorer. The youth are staring at a bleak future. The farmers are distressed. In the last decade alone, 1,12,000 farmers committed suicide. And for women, can the Government point out a single standalone scheme introduced that actually benefited them?

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI JOSE K. MANI: One minute, Madam. When we talk about the World Happiness Index published by the Oxford Wellbeing Research Centre, India ranked 126^{th} out of 143. Even India's neighbours like Nepal, Myanmar stand above us. ...*(Time-bell rings)*... Why are the people not happy?

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI JOSE K. MANI: Madam, I conclude by saying that the Budget is discriminatory, lacks vision and fails to address the core issues facing our nation. It is a Budget for the corporate and not for the common man. Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Shri Samik Bhattacharya, not present. Next speaker, Shri Ramdas Athawale, not present. Shri Iranna Kadadi, not present. Now, Shri K. Vanlalvena, five minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. VANLALVENA (Mizoram): Madam, I would like to support this new Budget. First of all, I want to mention about the Budget allocation for eight different States of the North East, only in the field of Ministry of Road Transport and Highways. Madam since I have only five minutes to speak, let me concentrate only in the field of Ministry of Road, Transport and Highways. The funds allocated for the States of North-East are as follows. Number one, in Arunachal Pradesh, the funds allocated is Rs. 5,327 crores; in Assam, Rs. 34,198 crores; in Manipur, Rs. 13,779 crores; in Meghalaya,

Rs. 7,219 crores; in Mizoram, Rs. 16,606 crores; in Nagaland, Rs. 10,643 crores, in Sikkim, Rs. 4,494 crores and in Tripura, Rs. 5,106 crores. The total for eight States of the North-East is Rs. 97,372 crores.

Madam, I would like to speak that this new Budget is not only for Andhra Pradesh and Bihar but it is also for the development of the North-East. Secondly, among the eight States of the North-East, Mizoram is the second highest of the road and highways budget holder under the Ministry of Road, Transport & Highways next to Assam. I express my heartfelt thanks to hon. Minister, Shri Gadkari*ji*.

In Mizoram, road transport is the most dominant means of transport because other means of transport such as railways and waterways hardly function since it is a hilly region. A good road network is vital to the economic development for the State of Mizoram. The total length of all types of roads in Mizoram is 9147 Kilometres among which 1470 Kilometres long is the National Highway. Most of them are under construction and most of them are to continue during this financial year. All the funds have been allocated for this new Budget. The ongoing works of the construction of 2-lane roads of NH-54, Aizawl to Tuipang Road which is 299 Kilometres long is under-construction and 74 per cent of the work is completed. Madam, we need 14 hours to reach Tuipang town from Aizawl in the past years, but now, we need only eight hours because of the Ministry of Road, Transport & Highways. But, it is still under construction. We need more funds this year.The funds required to complete this work is newly allocated. So, thank you very much. It is a great achievement under Modi*ji*'s Government for Mizoram.

Another new double-lane road that is 169 Kilometres which starts from Aizawl to Champhai which is on Myanmar border is also under construction and 92 per cent of the works has been completed. We used to take 10 hours before but now we need only five hours to reach Champhai town. It is because of whom? It is because of Modi*ji*'s Government.

Another new road Lunglei to Tlabung which is Bangladesh border is also under construction. The road stretch is 74.9 Kilometres long and 22 per cent is completed and another 78 per cent is still under construction which is to be finished next year according to the project. In the southern most part of Mizoram, the Ministry of Road, Transport & Highways had also declared new National Highway Longmasu to Zorinpui amounting to Rs. 489.01 crores of the project cost which is to be started this year. Another new road, Keifang to Tuivai, 183 Kilometres is also under construction. Aizawl bypass road amounting to Rs. 1,748.87 crores is also to be constructed soon. Lastly, the hon. Union Minister, Gadkari*ji* has also declared that Rs. 1,742 crores for the construction of Silchar to Aizawl 4-lane road which is to be started this year.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI K. VANLALVENA: In view of all these development works under the Ministry of Road Transport and Highways, the Union Budget for 2024-25 is good enough for the North-Eastern States, especially, for the State of Mizoram. Thank you.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now Shri Naresh Bansal. You have ten minutes.

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): धन्यवाद, मैडम चेयरपर्सन। सर्वप्रथम, माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बने और आदरणीया निर्मला सीतारमण जी ने सातवीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट देश का सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य, दूरदर्शी और visionary Budget है, विकसित भारत के 2047 का roadmap है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन समूहों को, जिनको ज्ञान के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्थापित किया है, इन सब के संबंध में ध्यान रखा गया है। बजट में विकास के 9 सूत्री विषय को शामिल किया गया है, जो कृषि में उत्पादकता और लचीलापन से लेकर अगली पीढ़ी के सुधारों तथा सर्वांगीण, समग्र कल्याण और विकास को समाहित करता है।

मैडम चेयरपर्सन, बजट पर चर्चा करते समय हमारे विपक्ष के मित्र बहुत कुछ बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी वह एनडीए की सरकार थी; 2019 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी वह एनडीए की सरकार थी और 2024 में भी जो एनडीए था, एनडीए के रूप में ही मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत की महान जनता से वोट माँगने गए थे और जनता के आशीर्वाद से एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पर जो तीन-तीन बार चुनाव में लोगों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे; विभिन्न प्रकार की बैसाखी और गठबंधन लेकर गए; अनेक प्रकार के * करने वाले narratives जनता के बीच में उन्होंने रखे; कभी कहा कि 400 आ गए, तो संविधान बदल देंगे; कभी कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे और यह तब कहा, जब उनका इतिहास यह बताने वाला है कि संविधान का सर्वाधिक दुरुपयोग अगर किसी ने किया, संविधान के साथ सर्वाधिक खिलवाड़ किसी ने किया, तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपात स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद श्री राजीव गांधी और उसके बाद की जो यूपीए की सरकार रही, हर सरकार में कुर्सी बचाने के लिए हमने संविधान के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा है। जिसमें पूरा बहुमत मिल रहा है, NDA का pre-poll alliance है, फिर भी यह कहा जा रहा है कि बैसाखी है। हम commitment के साथ गए और हमें commitment के साथ समर्थन मिला है।

मैं उत्तराखंड से आता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सौतेला व्यवहार कैसा होता है। माननीय चेयरपर्सन, बड़े आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य बना। कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के बड़े

* Expunged as ordered by the Chair.

नेता कहते थे कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड बना। विपरीत परिस्थितियों में भी स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहां विकास कर रही है। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के विकास के लिए भी हमें बहुत कुछ इस बजट में मिला है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और अपने वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन 2002 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, तब हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे उत्तराखंड के नेता उस समय के उत्तराखंड के मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी के साथ श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेई जी को मिले और उत्तराखंड के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज लिया और एक एम्स भी हमें मिला, लेकिन सौतेला व्यवहार कैसा होता है, मैं यह बताना चाहता हूं।

2007 में उत्तराखंड में जब हमारी सरकार आई और दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी, तो वह इंडस्ट्रियल पैकेज समाप्त कर दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि नया राज्य था, इनकी सरकार के समय हमने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, वह और 10 साल के लिए बढ़ाया जाता, लेकिन कांग्रेस ने उसको समाप्त कर दिया। इनकी सरकार के समय, अटल जी ने हमें जो एम्स दिया था, इन्होंने अपनी सरकार में 5 साल तक एम्स के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। यह है - सौतेला व्यवहार।

मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से सर्वांगीण विकास होगा। चूँकि हमारे उत्तराखंड में विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, वहां लैंडस्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, उसके लिए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा मिला भी है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं का दर्द झेलने वाले हिमालयी राज्य उत्तराखंड की चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के बजट में दिखती है। अपने भाषण में वित्त मंत्री जी ने उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय सहायता देने का जिक्र किया है। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा, वहीं प्रदेश में चार नयी परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। उत्तराखंड को इस बार बजट से रेल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ का बजट मिलेगा। बागेश्वर-टनकपुर, बागेश्वर-गैरसैण, ऋषिकेश-उत्तरकाशी और देहरादून-सहारनपुर रेलवे लाइनों की DPR बनाने का काम किया जा रहा है। देहरादून-हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला-काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम-किच्छा-कोटद्वार, लालकुआँ जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर सहित 11 स्टेशंस को 'अमृत स्टेशंस' के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2009-2014 में केंद्र में संप्रग सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड को रेल बजट के रूप में सालाना केवल 187 करोड़ रुपये मिलते थे। केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने के बाद बजट में लगातार वृद्धि होती गई। वर्तमान में यह बजट 27 गुना तक बढ़ गया है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री नरेश बंसल: मैडम, मैं conclude कर रहा हूँ। मैडम, उत्तराखंड में आज भी तीन से चार हजार गाँव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन बजट में 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के चौथे चरण

को शुरू करने का जिक्र प्रमुखता से हुआ है। यदि आबादी का मानक 100 से 200 का होता है, तो इससे हमारे राज्य में हजारों गाँवों तक सड़क पहुँचने का सपना पूरा हो सकता है। इस केन्द्रीय बजट से राज्य सरकार केन्द्रीय करों से 2,217 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के तौर पर प्रदेश के लिए 13,943 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को केन्द्रीय करों में 11,726 करोड़ रुपए की राशि राज्य के अंश के रूप में प्राप्त हुई थी। इन योजनाओं में पूरे पाँच साल बजट की कोई कमी नहीं होगी। कृषि, जलवायु अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्म की पैदावार, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, शहरों के इर्द-गिर्द औद्योगिक पार्कों की प्लग एंड प्ले योजना, शहरों के विकास की ब्राउन फील्ड योजना, बिजली बिल में कमी लाने के लिए सूर्यघर योजना, शहरी और ग्रामीण भूमि सुधार योजना, पीएमजीएसवाई में 12 मासिक सड़कों का विकास, आदि केन्द्र पोषित योजनाओं की बात की जाए, तो इस मोर्चे पर भी राज्य की झोली भरी नजर आएगी।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

श्री नरेश बंसल: मैडम, मैं conclude कर रहा हूँ। राज्य में 17 से अधिक केन्द्र पोषित योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें प्रदेश को 90-10, 80-20 के अनुपात में केन्द्रीय अनुदान मिलता है।...(**समय की घंटी**)... ऐसी योजनाओं में केन्द्र के बजट में भारी भरकम प्रावधान होने के चलते राज्य में वित्तीय भार को सहारा मिलेगा। मुद्रा लोन योजना में भी इसकी राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए किया गया है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

श्री नरेश बंसल : मैडम, मैं अंत में इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह बजट जहाँ पिछले 10 साल की मजबूत आर्थिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है, वहीं भविष्य की 2047 का रोडमैप भी है। इस प्रकार से इस बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The next speaker is Shri Iranna Kadadi; you have fourteen minutes.

SHRI IRANNA KADADI (Karnataka): †"Thank you, hon. Vice Chairperson, Madam, today I would like to thank you for allowing me to participate in this important discussion on the Union Budget 2024-25. I would like to thank the people of this nation along with the people of Karnataka who have given the opportunity to the

† English translation of the original speech delivered in Kannada.

Global Leader, Shri Narendra Modi and the Bhartiya Janata Party, to serve the nation for the third consecutive term. It is a matter of immense pride for the people of Karnataka that our Finance Minister, Smt. Nirmala Sitaraman, who represents the State of Karnataka in this august House, as she is the first female Finance Minister, to present the Union Budget for the seventh time in a row. I am telling you that... (*Interruptions*)...This Budget would enable us to realize the dream of Viksit Bharat by the year 2047. This Budget is aimed at welfare and benefits the four pillars of our society, that are the youth, women, farmers and the poor people. My friends from the Congress Party have been continuously mentioning that Karnataka did not get anything in this Budget. I would like to tell them that during the UPA regime from 2004 to 2014, the tax sharing was 81,791 crore and during the last 10 years of our Government it has increased to 2,85,818 crore with an increase of 262 percent. We do not believe in appeasement politics. I can proudly say that our Government is working to empower our farmers, and our policies are in place to ensure the same.

Today in this competitive world, we can provide our next generations with good clothes, good education, good cars and all the comforts of life, but if they don't get quality nutrition, all the facilities are wasted. Our Government under the visionary leadership of Shri Narendra Modi has rolled out various schemes in the last 10 years and the same would continue further.

Our Government has allocated 1.52 lakh Crores for agriculture related sectors. We are providing our farmers with quality seeds. Not only that, for the next two years, 1 crore farmers across the nation would be trained to take up organic farming. We are of the firm belief that farmers must work with the nature and protect it at the same time. In order to bring these fundamental changes in farming techniques, we ensure that our farmers receive accurate weather information, crop suggestions, 109 hybrid quality seeds. And important information regarding the market have been provided to farmers digitally. In order to facilitate the farmers, 10,000 bio-input centers have been established across the country. I would also like to highlight that 100 districts have been getting the benefits of the digital survey. PM Kisan Samman Nidhi Scheme has provided 11.8 crore farmers with Rs.6000 financial aid; out of them all, 22% are women. I want to remind my opposition friends from Karnataka that we used to give Rs. 4000 to farmers along with Rs.6000, which were stopped after your Government came to power in the State of Karnataka. Not only that, we were also giving incentive to dairy farmers in the form of rupees 5 per litre of milk. But after you came to power, you have not increased it even by Re. 1. You have meted out this injustice to the farmers. Today those who are often seen criticizing us, what have they done? They have withdrawn 11,000 crore rupees from the Scheduled Tribes funds and they have

misused it for fulfilling their election promises. I want to remind you that the State Government has transferred 187 crore Rupees from Maharishi Valmiki Scheduled Tribe Development Corporation and they have misused these funds for the election expenditure of their party candidates in the Lok Sabha elections.

Madam, we do understand that our youth today will be the leaders in future. So our Government has given special importance to the youth. Financial assistance up to 10 lakh for higher education will be provided from the Central Banks at 3% interest rate. You have to understand what I am saying...*(Interruptions)*...Internship will be provided to 21.4 crore youths for a period of 5 years at an expense of Rs. 2 lakh crore, for their employment and skill development. To ensure skill development and employment, the Central Government has announced five packages...(*Interruptions*)... Both of my friends are from Karnataka and they can understand Kannada...(*Interruptions*)...One month's salary will be provided to those joining the jobs for the first time. The Government will help in getting provident fund for youngsters who have the Start Ups, for a period of 4 years, in order to create employment. Those earning a salary of less than Rs. 1 lakh will be given a sum of Rs. 3000 as provident fund for a period of 2 years. With the cooperation of the State Governments and industrialists, 20 lakhs youth will be given skill training for a period of 5 years under the Skill Development Programme. The Government is to start an integrated scheme for a period of 5 years to give internship opportunities to 1 crore youth.

Madam, under the able leadership of Shri Narendra Modi, we have always given importance to the Nari Shakti. Our Government passed the Nari Shakti Vandan Bill and has extended the reservation to women in the legislature. Madam, 3 lakh crore rupees is earmarked for women empowerment in this Budget. The Government has prepared various skill development programmes in order to encourage the participation of women in various sectors. In the financial year 2024 there is a 24% increase in the employment of women. Madam, 10.32 crore women have benefited from the LPG cylinder scheme, that is, the Ujjwala Yojna. Out of 52.5 crore Jan-Dhan accounts, 56% account holders are women.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRI IRANNA KADADI: This Budget is dedicated to women, youth, farmers and the poor people. I wholeheartedly support this Budget. I thank the Government for this visionary Budget. Namaskar

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, hon. Member, Shri Kartikeya Sharma. You have 10 minutes.

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Hon. Vice-Chairperson, I extend my sincere gratitude to you for allowing me to express my views on the Union Budget 2024-25, presented by the hon. Finance Minister. As an Independent Member of this august House, I rise today to offer my support for the Budget, in the favour of the Budget. मैं अपनी बात रखने से पहले स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था - 'संपूर्ण जगत की शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं, जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है।'

महोदया, जगत के प्रबुद्ध लोग इस शक्ति को देख पा रहे हैं। मैं Amazon के फाउंडर Jeff Bezos को क्वोट करना चाहता हूं - "I predict that the 21st Century is going to be the Indian Century. The dynamism, energy, I see, everywhere I go here, people are interested in self-improvement and growth. This country has something special. This is going to be the Indian Century." ऐसे ही मैं और एक प्रबुद्ध व्यक्ति founder of Microsoft, Bill Gates को क्वोट करता हूं - "The strength of India today in terms of economic growth, innovation is very exciting. Democracy is a magic system when it works well." I would also like to quote a very important statement made by the World Bank. The World Bank in its latest India Development Update, a World Bank flagship publication, says and I quote: "India's economy has demonstrated resilience despite a challenging external environment." Sir, Auguste Tano Kouame, who is also the Country Director for India in the World Bank says and I quote: "India's economy has been remarkably resilient to the deteriorating external environment, and strong macro-economic fundamentals have placed it in good stead compared to the other emerging market economies." Not only this, Mr. Dhruv Sharma, a senior Economist, who is the author of this report also says and I quote: " A well-crafted and prudent policy response to global spillovers is helping India navigate global and domestic challenges." Sir, there are umpteen number of these instances like the SKOCH Report, which talks about "Employment generative impact of ModiNomics: The Paradigm Shifts." It goes on to say that there have been 1.98 crore employments per year, according to the SKOCH report that has been generated. The IMF and its Managing Director, Kristalina Georgieva, remarked and I quote: "India deserves to be called a bright spot in this otherwise dark horizon because it has been a fast growing economy, even during these difficult times, but most importantly; this growth is underpinned by structural reforms." While the Opposition is failing to acknowledge the real benefits this Budget brings to our people, their focus on criticism rather than the constructive dialogue seems aimed at hiding the truth and misleading the public.

Madam, I would like to highlight some key points of the Union Budget which will demonstrate how the economy and the Budget have played a pivotal role in today India's progress. The Budget has highlighted that India has shown an impressive economic growth of 8.2 per cent despite global economic struggles. The social sector expenditure has doubled, from nearly 11 lakh crores to 23 lakh crores in 2023-24. Additionally, the health sector spending has almost doubled since 2017-18, increasing from 2.5 lakh crores to 5.85 lakh crores. Sir, Haryana, the State I come from, has also benefitted from the special assistance for capital expenditure/investments provided under the Budget. There are 3,195 crores which have been given to the State of Haryana between 2020 and 2023. In the financial year 2024-25, Haryana received a total of Rs.13,632/- crores, an allocation of 1.093 per cent from the distribution of net proceeds of the Union taxes and I would like to thank the Government for that.

Madam, yesterday, a very senior leader spoke about paper leak, and he said that there was not much in the Budget about the paper leak. We all know that the Budget is not about paper leak. But I would like to profusely thank the Government and the hon. Prime Minister that they have managed to have ten successful Budgets without any Budget leak because in the previous Governments, the Budgets would also leak. So, that is an achievement that this Government has managed to achieve. *...(Interruptions)...*

Madam, much has been said by my previous speakers on the Budget. *...(Interruptions)...* Some lauded it for its farsightedness or some of us also praised it as fiscally-prudent document while some suggested modifications. *...(Interruptions)...* Some even complained about lack of attention towards a particular sector. *...(Interruptions)...* Even the industry leaders welcomed the Budget with open arms. *...(Interruptions)...*

Madam, however, something was missing unless our learned speaker and hon. former Finance Minister who I hold in high esteem stood up and expressed his views. *...(Interruptions)...* Hearing his opinions, I am reminded of an appropriate *sher* by Gulzar Sahab. *...(Interruptions)...*

"जिंदगी की दौड़ में, एक तुम ही फुरसत में हो,
सालों पहले जैसा देखा था, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो।"

Madam, the hon. Member's level of optimism has remained unchanged from his Budget speech in 2017. Casting doubt on the future of digital transactions in India, not only did he dismiss its functioning but also looked down upon the capabilities of our citizens, particularly, the female vegetable vendors. It was these same small

vendors that proved him wrong when India accounted for 46 per cent of all digital payments in the world and UPI transactions now account for 80 per cent of all digital payments in India.

Madam, I hope on his monthly travel when the hon. former Finance Minister … …*(Interruptions)*… Please listen. You will be better informed. I hope on his monthly travels of …*(Interruptions)*… Hon. Chair, I will request you to ask the Members not to disturb.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please continue.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Madam, I hope on his monthly travels, the hon. former Finance Minister, will look out of the window and see that in every nook, crany and corner of this country; you will find digital transactions happening.

Madam, as per the Government's Economic Survey, the growth rate is projected at seven per cent. The same forecast is being done by agencies like the IMF. Let us assume what he said is the truth. The wrong deflators are being used by the Government to fudge the growth rate. Does he intend to say that even international institutions are erring in their projections? As senior Opposition leaders, they are expected to give constructive criticism and not fuel doubts amongst the citizens.

Madam, it is a great misfortune that a noble scheme of giving free ration during the distressing times of Covid was attempted to be labelled as a flag-bearer of economic crisis in India. I ask the Members what are their opinions on the Programmes like Fome Zero which is also called Zero Hunger, a programme run by the Government of Brazil or Diconsa, a programme which is run by the Government of Mexico, emphasising on giving free or subsidised ration to its needy citizens. Even a super power like the US runs the Supplemental Nutrition Assistance Programme called SNAP providing assistance to low-income families to purchase eligible food in authorized retail food stores.

Madam, we should be proud that India despite its limited resources and difficult times has been able to feed over 80 crore citizens through *Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana.*

Madam, there was also this talk of *Badla Lo, Kursi Bachao*. Various sorts of statements were passed. I don't want to get into these but I would definitely like to say that these are times where a country looks up to both the Houses, and, especially, our House, the House of Elders. We must set a precedent and an example as to what can we bring to the table to add to the problems that exist at hand. We

must use this opportunity to communicate this to the polity of the country because they have a lot of faith in us.

Madam, another esteemed colleague, a senior esteemed colleague, spoke about taxes like England and services like Somalia. Why are we trivialising another country's progress, problems and challenges? Through the Chair, I would like to ask the august House, is this the kind of debate we want in the House of Elders? What kind of a message are we sending to a friendly nation with which we have shared strong diplomatic ties for 64 years? This is not our *Bhartiya Sanskriti* to look down upon anyone. I even request the Chair to expunge these remarks. *...(Interruptions)...* And, Madam, let us look at the number of some basic commodities. *..(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please continue. *...(Interruptions)...*

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Hon. Chair, I will seek your indulgence so that I can complete my speech. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PHANGNON KONYAK): Hon. Member, Dr. John Brittas, please take your seat. *...(Interruptions)...* Please take your seat.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Hon. Chair, I will seek your indulgence so that I can complete my speech.

Let us look at the numbers of some basic commodities since we are talking about the differences between England, Somalia and the taxes in India. Madam, in India, the cost of one litre of milk is Rs. 56-57; in Somalia, it is Rs. 140. A bottle of *Coca Cola* costs Rs. 60 in Somalia; in India, it is Rs. 32. The cost of bread in Somalia is Rs. 81; in India, it is Rs. 38.70. The cost of apples is Rs. 380 per kilogram in Somalia; it is Rs. 110 in India.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, you have only ten seconds to conclude.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Madam, I will seek the indulgence of the hon. Chair to complete my speech. I am an Independent Member. I don't have a party to take time from. So, kindly oblige me.

Madam, what do we get in return is a question which is asked by the Opposition. Just to put things in perspective, the population of England is almost 5.6 million. The size of the world's biggest healthcare programme, which is also known as the Universal Healthcare Program, is almost 89 times the size of England. That is what we get in return. We get the *Pradhan Mantri Awas Yojana*, which is the world's largest affordable housing project. We get the largest direct benefit scheme in the world in the form of the *Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi*. We also get the *Sarva Shiksha Abhiyan*, one of the largest educational programs in the world.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, you have 20 seconds to conclude. Please conclude.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Hon. Chair, I would like to seek your indulgence. I would like to complete my speech. I am an Independent Member. I don't have a party to take time from. Please oblige me.

Madam, another point that has echoed a lot in this Chamber is how the hon. Finance Minister has not taken the names of many States. Allegations have been made that the focus was on Bihar and Andhra Pradesh.I looked at all the budget speeches from 2004 to 2014. Not once in these ten years did the UPA Government mention more than the names of six-seven States. States like Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan were conveniently ignored. Interestingly, not mentioning BJP ruled States is still understandable, but during the UPA *raj*, even the State of Tamil Nadu did not find any mention in six budget speeches out of the ten. *...(Time-bell rings)...*

Madam, I am just concluding.

Since when has not mentioning a State's name become a parameter for allotting resources to it? I want to conclude by saying that my State is Haryana; it was not mentioned in the Budget, but it got Rs. 13,632 crore. I want to acknowledge and thank the hon. Prime Minister and the Finance Minister for doing this much. *...(Interruptions)...*

Jai Hind! Jai Bharat!

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Shri Brij Lal; 14 minutes.

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की लगातार तीसरी सरकार के पहले बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, साठ वर्ष बाद भारतीय गणतंत्र में यह तीसरा अवसर है जब मोदी जी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक अभूतपूर्व बात है। महोदया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 99 पाए हैं और वे अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को लगातार तीन संसदीय चुनावों में कुल 195 लोक सभा सीटें प्राप्त हुईं, जो 2024 में बीजेपी को प्राप्त 240 सीटों से भी 45 सीटें कम हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश में नैरेटिव फैलाते रहे। उपसभाध्यक्ष महोदया, इन्होंने संविधान बदलने और आरक्षण छीनने का फर्जी नैरेटिव बनाया। महोदया, मैं दलित हूं, लेकिन इनके द्वारा दलितों को * किया गया।

महोदया, इसी तरह का एक और फर्जी नैरेटिव जब शाहीन बाग में सीएए का हुआ था, तो महोदया, वह फर्जी नैरेटिव पीएफआई ने रचा था। पीएफआई बनी थी-- National Development Fund of Kerala, Karnataka Forum for Dignity, *Tamil Manila Pasarai* terrorist organizations और उस ऑर्गेनाईजेशन में -- उपसभाध्यक्ष महोदया, सीएए में 75 परसेंट नागरिकता उन दलितों को मिली थी, जो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से भागकर आए थे। महोदया, वहाँ पर दलितों को * करने के लिए बाबा साहेब के फोटो, हाथ में संविधान और राष्ट्रीय झंडा था। महोदया, वह संगठन कौन था? वह पीएफआई था। मैं नरेन्द्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन को बैन किया। यह वही पीएफआई है, जब एनआईए ने पटना में रेड की, तो हम तो 2047 में भारत को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं और वहाँ 2047 तक भारत को गजवा-ए-हिंद का रोडमैप मिला था। महोदया, वह पीएफआई है। इन्होंने जो फर्जी नेरेटिव रचा, तो ये नेरेटिव रचने के माहिर हैं। यह वायरल है, जो पूरा फर्जी शामिल हुआ है। महोदय, यह बाबा साहेब का अपमान है। दलितों का अपमान है। आदिवासियों का अपमान है कि फर्जी नेरेटिव बनाया गया। महोदया, इन्होंने एक फर्जी नेरेटिव और बनाया। कॉंग्रेस पार्टी के माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि साल में एक लाख और जुलाई से 8,500 खटाखट! वह खटाखट कहाँ चला गया? यह काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। दोबारा यह नेरेटिव नहीं चलने वाला है। आपने यह नेरेटिव गढ़ा है।

महोदया, अब मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। ये salient फीचर्स हैं। मैं बताना चाहता हूँ। नंबर एक - मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़, एनर्जी सिक्योरिटी को बड़ी प्राथमिकता। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के लिए 4.01 लाख करोड़। पाँच साल में 4.01 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज। पाँच साल में रोजगार पर 2,00,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता। एक करोड़ किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर। 10,000 बायो-रिसर्च सेंटर। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन। पाँच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लाँच होगा। तिलहन-दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए मिशन लाँच होगा। 20

* Expunged as ordered by the Chair.

लाख युवा पीएम योजना के तहत स्किल्ड होंगे। देश की टॉप 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप व्यवस्था। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे।

महोदय, पिछले दस साल में मोदी जी का जो सुशासन रहा है, तो भारत देश की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और हम 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हैं। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, आज जहाँ दुनिया के विकसित देशों में जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम हो गई है, कहीं-कहीं तो निगेटिव है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत सालाना की गति से आगे बढ़ रही है। 2004 में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 12वें स्थान पर थी। 2004 में यूपीए सरकार आई थी और दस साल में यूपीए सरकार की अर्थव्यवस्था 2014 में केवल एक अंक बढ़ी। महोदया, यूपीए सरकार की अर्थव्यवस्था कछुआ नहीं, बल्कि घोंघे की चाल से आगे बढ़ रही थी। वही मोदी सरकार में अब दस साल में 11वें स्थान से उड़ान भरते हुए, पाँचवें स्थान पर आ गई है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIR CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please don't interrupt. ...(*Interruptions*)...

श्री बृज लाल: उपसभाध्यक्ष महोदया, पिछले दस सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में वृद्धि हुई है। इसमें दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं हैं, जो सफल हुई हैं। मैं जन-धन अकाउंट के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा। मैं ग्रामीण हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज जन-धन अकाउंट नहीं होता, तो उस एक रुपये में जो 15 पैसे पहुंचते थे, एक रुपये के सौ के सौ पैसे नीचे नहीं पहुंचते हैं, सब लोग खा जाते हैं, यह तो माननीय राजीव गाँधी जी ने ही कहा था।

उपसभाध्यक्ष महोदया, प्रश्न यह उठता है कि यह डेवलपमेंट कैसे हुई? मोदी जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है - कानून व्यवस्था। जब किसी देश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, यह चाक-चौबंद होती है, तब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please don't interrupt. ...(*Interruptions*)...

श्री बृज लालः यूपीए सरकार में क्यों होता था? ...(**व्यवधान**)... यूपीए सरकार में रोज आतंकवादी घटनाएं करते थे। ...(**व्यवधान**)... मैं तथ्यों पर बोल रहा हूं। यूपीए सरकार में हमारे पर्यटन स्थल पर बमबारी की जाती थी। ...(**व्यवधान**)... जयपुर ब्लास्ट, 13.5.2008 को 80 मरे, 216 घायल। सरोजनी नगर, दिल्ली में यहां धनतेरस के दिन ब्लास्ट हुआ था और 62 लोग मारे गए थे। ...(**व्यवधान**)... कनॉट प्लेस, गफ्फार मार्किट 13.09.2008 दो दर्जन लोग मारे गए थे।

डा. सैयद नासिर हुसैन: बजट पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री बृज लालः हाई कोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहा। ...(**व्यवधान**)... 7 सितम्बर, 2011 को 15 मरे और 79 घायल। मैं बटला हाउस का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। 13.9.2008 इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हुए थे और इंडियन मुजाहिद्दीन का नॉर्थ इंडिया कमांडर आतिफ आमीन और उसका साथी साजिद मारा गया था। ...(**व्यवधान**)... जब यह घटना हुई, तो कांग्रेस एक बड़े नेता, मुझे दुख है कि वे यहां मौजूद नहीं हैं, राज्य सभा के सांसद हैं ...(**व्यवधान**)... मैं बजट पर बोल रहा हूं, आप क्यों यहां ...(**व्यवधान**)... यह क्यों होता था? आपके वह नेता जो एक प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, वो आजमगढ़ गए वह संजरपुर जो नॉर्थ इंडिया कमांडर, इंडियन मुजाहिद्दीन का हेडक्वार्टर था, ...(**व्यवधान**)... शहजाद एक अपराधी था। मैंने पकड़कर दिया था, तब मैं वहां का एडीजी चीफ होता...(**व्यवधान**)... उसको जब दिल्ली से आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो आपके एक बड़े नेता महोदय बोले कि नहीं, इसमें तब भी ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

आपके एक नेता, जो बहुत बड़े नेता हुए, 10 फरवरी, 2012 को इलेक्शन में भाषण देने गए थे, उन्होंने कहा था कि बटला हाउस की तस्वीर देखकर उनकी नेता रोई थीं। ...(**व्यवधान**)... इतना बड़ा नेता जो विदेश मंत्री रहा हो और उसके मुंह से यह बात निकलेगी, तो क्या मैसेज जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस राज में जर्मन बेकरी ब्लास्ट ...(**व्यवधान**)... धार्मिक प्लेस में दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकटमोचन ब्लास्ट, शीतलाघाट ब्लास्ट, यूपी कचहरी ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, गोलघर गोरखपुर ब्लास्ट, बोधगया ब्लास्ट, लुम्बिनी पार्क, गोकुल चाट, हैदराबाद ब्लास्ट ...(**व्यवधान**)...

महोदया, टेररिस्ट ने हमारी आर्थिक राजधानी को टारगेट किया था। ...(**व्यवधान**)... मुम्बई सीरियल ब्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, 26/11 आतंकवादी हमला, इसमें हमारे दो आईपीएस ऑफिसर और मेजर उन्नीकृष्णन मारे गए थे। ...(**व्यवधान**)... इसमें एक नेता आपके अजीज बर्नी से किताब लिखाई गई, उसका नाम था आरएसएस की साजिश-26/11...(**व्यवधान**)... कहा गया था, भगवा आंतकवाद है। कसाब को कहा गया कि वह निर्दोष है, पाकिस्तान निर्दोष है। ...(**व्यवधान**)... यहां जब आतंकवादी घटनाएं होती थीं, तो विदेश से एडवाइजरी जाती होती थी कि भारत मत जाइए, भारत असुरक्षित है। ...(**व्यवधान**)... भारत का विकास नहीं होता और इसीलिए यहां की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई थी। ...(**व्यवधान**)...

MS. SUSHMITA DEV: He is not speaking on the Budget. *...(Interruptions)...*

श्री बृज लालः उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अब नक्सलवाद पर बात करना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)... नक्सलवाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। जब 2014 में मोदी जी आए, तो 106 जिले प्रभावित थे। ...(**व्यवधान**)... 2024 में घटकर उनकी संख्या 32 रह गई है। नेपाल से लेकर दक्षिण तक रेड कॉरिडोर उनकी कर्बला थी। बूढ़ा पहाड़, चकरबंधा, ये तमाम ऐसी जगहें थीं, जो नक्सलवादियों के अड्डे थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे। सीआरपीएफ ने Operation OCTOPUS चलाया और जहां तीन-तीन दशक से कब्जा था, उसे वे छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ...(**व्यवधान**)... बूढ़ा पहाड़ पर 2023 में कब्जा किया गया है। ये क्यों पनपे? ...(**व्यवधान**)... आपके भी नेता शुक्ला जी मारे गए थे।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। ...(**व्यवधान**)... नक्सलवाद एक दिन में नहीं फैलता है। महोदया, मैं एक नक्सलवादी से इंटेरोगेशन कर रहा था, तब उत्तर प्रदेश का स्पेशल डीजी था...(**व्यवधान**)...

7.00 P.M.

वह इसी JNU का पढ़ा हुआ M.Phil. और Ph.D. था। मैंने उससे पूछा कि तुम मध्य प्रदेश में कैसे सफल हो गए, तुमने बिहार में कैसे बेस बना लिया, छत्तीसगढ़ में कैसे बेस बना लिया, तो उसने कहा कि वहाँ न तो विकास था, न सरकारी एजेंसी जाती थी, there was a vacuum and we occupied it. लेकिन मोदी सरकार में क्या हुआ है कि there is no vacuum. Development है, सड़कें बनाई गई हैं, community policing की गई है और आज वहाँ पर vacuum नहीं है। ...(**व्यवधान**)... वहाँ विकास से उस vacuum को भर दिया गया है। ...(**व्यवधान**)...

महोदया, अब बात आती है कि उस समय हमारे जवान क्यों मारे जाते थे? ...(**व्यवधान**)... जो सुकमा में मारे गए, दंतेवाड़ा में मारे गए, सीआरपीएफ के 76 जवान एक साथ मारे गए थे। मैं प्रदेश का ADG था। उनकी लाशें, ताबूतें, तिरंगों में लपेट करके चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आती थीं और मैं उनको receive कर रहा था। महोदया, उनमें बिहार का एक जवान था, जब उसको गोली लगी, उसने अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा कि क्या कर रही हो, उसकी पत्नी गेहूँ काट रही थी, मार्च का महीना था और उसके बाद उसको गोली लगती है। वह मर गया, वह शहीद हो गया। महोदया, इसी JNU में जश्न मनाया गया था कि ये दुश्मन हैं। महोदया, मैं बताऊँ कि उस समय हमारे पास equipments नहीं थे। जब मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, उस समय Second World War की लड़ी हुई 303 राइफल थी। National Police Academy, हैदराबाद, जो Premier Training Centre है, मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। लेकिन मैं अमित शाह जी का, प्रधान मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारी फोर्सेज़ को modern equipments दिए गए हैं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री बृज लाल: आज हमारे पास Carl-Gustaf और rocket launchers हैं। आज हमारे पास AK-203 है, rocket launcher है। महोदया, आज हमारे पास एक और weapon है, जिसकी वजह से हम forward base बनाने में कामयाब हुए हैं। ...(**समय की घंटी**)... पहले कोई घुसता नहीं था।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री बृज लाल: महोदया, मैं दो मिनट लूँगा। यह weapon है - WhAPC (Wheeled Armoured Personnel Carrier). यह अभी 2023 में अमित शाह जी ने उपलब्ध कराया है। यह ऐसा weapon है, जो amphibian भी है, हर terrain में चल सकता है। उसमें हमारे 4-5 जवान अंदर बैठते हैं,

ड्राइवर आगे बैठता है, ऊपर mount होती है medium machine gun. कितनी गोलियाँ चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब वह आगे चलती है, तो नक्सलवादी देख कर भागते हैं। ...(**समय की घंटी**)... मैंने उनका intercept सुना। नक्सलवादी कह रहा है कि कहीं भैंसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, काला भैंसा। आज उसकी वजह से हम forward base में घुस कर अपने bases बना रहे हैं, वहाँ हमारे जवान पहुँच गए।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री बृज लाल : महोदया, मुश्किल से साल भर का समय है। वह जो हमारा WhAPC है, जिसको नक्सलवादी भैंसा कहता है, जब वह चलता है, तो वे देख कर दूर भागते हैं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री बृज लाल: महोदया, याद करिएगा, एक से डेढ़ साल का समय है, इस देश से पूरा नक्सलवाद खत्म होगा। आपके समय आतंकवाद बढ़ता था, नक्सलवाद होता था।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Next speaker is Shrimati Mahua Maji. You have five minutes.

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): धन्यवाद, ऑनरेबल मैडम। इस बार के बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने रेल पर एक शब्द भी नहीं बोला। आज सुबह एक और रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा से मुंबई जाने वाली मेल का झारखंड में जमशेदपुर के पास सरायकेला में accident हुआ। 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। ...(**व्यवधान**)... 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, derail हो गए, दो लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। ...(**व्यवधान**)... लगातार रेल दुर्घटनाएँ होती जा रही हैं। इसके पहले वेस्ट बंगाल में हुई, उसके पहले ओडिशा में हुई। तमाम जगहों पर रेल दुर्घटनाएँ हो रही हैं, रेल बेपटरी हो रही है। हमारे देश की जो रेल की पटरियाँ हैं ...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, kindly speak on the Budget. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती महुआ माजी: यह बजट पर है। ...(**व्यवधान**)... हमारे यहाँ की रेल पटरियाँ जर्जर हो गई हैं, उनकी मरम्मत की जरूरत है। ...(**व्यवधान**)... रेल की पटरियों पर ध्यान दिया जाए। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ वंदे भारत जैसी ट्रेन लाने से नहीं होता है, हमारे देश की 90 परसेंट जनता ट्रेन से travel करती है। उनके लिए बोगियाँ बढ़ाई जाएँ। जिस तरह से वे ट्रेन में लटक कर exam देने जाते हैं, festivals में अपने घर लौटते हैं, आखिर इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता?

यह हमारी lifeline है। यह हमारी लाइफ लाइन है और रेल पर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। ...(**व्यवधान**)... झारखंड के ऐसे शहरों में, जहां दुर्गम पहाड़ी- पठारी क्षेत्र हैं, लोग शहर तक जा नहीं सकते, इसलिए वहां पर लोकल ट्रेन की भी जरूरत है, लोकल ट्रेन के लिए भी बजट बनाया जाए, ताकि उनको रोजगार मिले और ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो, माइग्रेशन की समस्या खत्म हो। ...(**व्यवधान**)... केंद्र सरकार आदिवासी हितों की बात तो करती है, मगर उनकी मांगों को, उनकी भावनाओं को समझ कर उनके अनुरूप बजट में उनके लिए प्रावधान नहीं बनाती। असम में पिछले 100 साल से भी अधिक समय से झारखंड के संथाल, उरांव और कई अन्य जनजातियाँ रहकर पीढ़ियों से काम कर रही हैं। उन्होंने वहां चाय के बागानों में काम किया, जंगल काटकर चाय उत्पादित किया। उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग 100 साल से हो रही है, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं दिया गया कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़ जाए। सरकार को पैसे की इतनी चिंता है। ...(**व्यवधान**)... उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, जबकि वहां पर उनकी कई पीढ़ियां हैं, उनके बच्चे वहां पर हैं। वहां पर लगातार खूनी संघर्ष हो रहे हैं। उन खूनी संघर्षों को रोका जाए। उनके लिए बजट बनाया जाये, उन्हें आरक्षण दिया जाए। उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। उनके साथ सौतेला व्यवहार न हो। मुझे लगता है कि जब राज्यों को सशक्त करेंगे, तभी देश सशक्त होगा और राष्ट्र सशक्त होगा।

हमारे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार से बार-बार हमारे माननीय मुख्य मंत्री मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें दिया नहीं जा रहा है, ताकि वे राज्य का विकास न कर सकें। ...(**व्यवधान**)...हम लोग पूरे देश को मिनरल्स सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। केंद्र सरकार ने Forest Conservation Bill लाकर आदिवासियों की आजीविका, जो वे जंगल से जुगाड़ करते थे, उसको खत्म कर दिया है। अब उनके लिए अलग से बजट बनाया जाए, ताकि उससे वे रोजगार कर सकें और अपना पेट भर सकें।

हमारे संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति-धर्मों के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। झारखंड में भी दुर्गम जंगली पहाड़ी इलाकों में जा-जाकर शताधिक वर्षों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलकर मानवता की सेवा मिशनरियों ने की है। लेकिन, अब सरकार ने आते ही FCRA बंद करके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों का पैसा रोक दिया है, जिसके कारण वे टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप सभी जानते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कितनी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। उन्होंने Sacred Heart Convent Anglo India Higher Secondary School, Villupuram से पढ़ाई की है। फिर, माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी Don Bosco से पढ़े हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहां से पढ़कर आज इस लायक बने हैं कि हम सब यहां बैठ पाए हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसे में, मैं अनुरोध करूंगी कि आपने ईसाई मिशनरियों के लिए जो FCRA बंद किये हैं, जिसके कारण प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पुनर्विचार किया जाए और जो बंद FCRA है, उनको देकर-- क्योंकि वहां हिन्दू और अन्य सभी जाति-धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। वहां कोई भेदभाव

नहीं होता। अगर भेदभाव हुआ होता तो आज हम और आप सभी लोग क्रिश्चियन बन गए होते। इसलिए FCRA जो बंद किया गया है, उसको फिर से चालू किया जाए। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

श्रीमती महुआ माजी: इसके अलावा, मेरी मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। हमारे राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। ...(**व्यवधान**)...यह बुढ़ापे की लाठी है, सरकार इस पर बजट बनाए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, you have ten seconds to conclude.

श्रीमती महुआ माजी : मैडम, मैं कहूंगी कि झरिया, धनबाद और करकट्टा कोयलियरी में जमीन के नीचे आग लगी हुई है, जिसके कारण गांव के गांव उजड़ रहे हैं। उनके लिए बजट बनाकर उन्हें बुझाने की तैयारी की जाए। ...(**समय की घंटी**)... देश का कीमती कोयला जल रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। माइनिंग एरिया में भी... ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Next speaker is Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. You have ten minutes.

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने 23 जुलाई को जो बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। महोदया, यह बजट एक विज़नरी बजट है, भारत को विकसित भारत की तरफ मजबूती से बढ़ाने के लिए तैयार किया हुआ यह बजट है। उपसभाध्यक्ष जी, हम सब पिछले छः दिन से विपक्ष को सुन रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन : मैडम, इनकी पार्टी का टाइम ...(**व्यवधान**)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, kindly do not interrupt. ...*(Interruptions)*... Please speak. ...*(Interruptions)*...

श्री सैयद नासिर हुसैन: मैडम, आप इनको extra time कैसे दे सकती हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री धनंजय भीमराव महादिक: मैडम, विपक्ष के सभी लोगों की बातें हम सुन रहे थे। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कोई भी खुश नहीं था। सब के सब यही बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला। यहां तक कि तमिलनाडु और बिहार वाले विपक्ष के साथी भी बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला और हद तो तब हो गई, जब सदन के एक सदस्य, जो देश के एक बहुत बड़े वकील हैं, वे वहां से बोल रहे थे, India's economy is in crisis. क्राइसिस किसे कहते हैं? हमारे आस-पास के पड़ोसी

देशों को देखिए, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि वहाँ पेट्रोल अभी ढाई सौ रुपए प्रति लीटर हो गया है, एक आटे की बोरी निकलती है, तो 100 लोग उसके पीछे भागते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया और बोले कि मैं यह देश चला नहीं सकता हूँ। उसे क्राइसिस कहते हैं। उन्होंने यहां पर जो आपत्ति जताई कि हमारे देश में क्राइसिस चल रहा है, मैं उस संबंध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2014 में 11वें स्थान पर था, आज वह पांचवें स्थान पर है। यह पांचवें स्थान पर कैसे आया? यह इसलिए आया, क्योंकि यह देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है।

मैडम, हमने देखा कि 2017 में जब जीएसटी कानून लाया गया था, तब जीएसटी का महीने का कलेक्शन 35,000 करोड़ रुपए था। अगर हम पिछले महीने, यानी जून, 2024 महीने का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे, तो यह पाएँगे कि 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यह कैसा क्राइसिस है? यह मैं उनसे जानना चहता हूँ। देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 से पहले सिर्फ साढ़े तीन सौ थी, आज भारत में 1,07,000 स्टार्टअप्स हैं। जिनमें कई सारे रोजगारों की भी संधी उपलब्ध कराई गई है। मैडम, इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या दो गुनी हो गई है। वहाँ से बहुत बार पर-कैपिटा इनकम की बात हुई। 2014 से पहले हमारे देश के लोगों की पर-कैपिटा इनकम 76,000 रुपए थी, आज वह 2,12,000 रुपए हो गई है। यह कैसा क्राइसिस है? यह हम जानना चाहते हैं।

मैडम, मैं कुछ और आंकड़े बताना चाहूंगा। यह महंगाई की भी बात करते हैं, क्राइसिस की बात करते हैं। हमारे देश में 2014 से पहले 2013-14 के साल में 18 लाख फोर व्हीलर्स की बिक्री हुई थी और आज 2024 में 42,18,746 फोर व्हीलर्स की बिक्री हुई है, यानी कि इसमें चार गुना बढ़ोतरी हुई है। यह कैसा क्राइसिस है? यह हम जानना चाहते हैं। 2014 में 1,14,000 टू व्हीलर्स की बिक्री हुई थी और आज 2024 में उसकी संख्या 17,97,400 है। इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। यह कैसा क्राइसिस है? अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात करें, तो पिछले एक साल में 9,10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हुई है। यह कैसा क्राइसिस है?

मैडम, हमारे देश में टूरिज्म बढ़ रहा है। यहां पर टूरिज्म के आँकड़े दिए गए। विदेशों से हमारे देश में जो लोग आते हैं, उनके आंकड़े बताए गए, लेकिन हमारे देश से विदेश में जो गए, उस संबंध में मैं आपको सिर्फ 2024 का आंकड़ा बताना चाहता हूँ, पहले मैं 2014 का बताऊंगा। 2014 में भारत से विदेश में यात्रा करने के लिए डेढ़ करोड़ लोग गए थे, 2024 में यह संख्या 7.5 करोड़ है। मैडम, लोगों की एक्सपेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है। देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे और आज देश में 149 एयरपोर्ट्स चल रहे हैं। 2014 से पहले देश में एयरलाइन के जो रूट्स थे, उनकी संख्या 209 थी और आज 605 रूट्स हैं। सबसे मजे की बात तो यह है, जिसको आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आज आप एयरलाइन का कोई भी टिकट खरीदने जाइए, तो टिकट मिलता नहीं है, सारे फ्लाइट्स फुल चल रहे हैं। 609 रूट्स डॉमेस्टिक की चल रही है और सबसे पहले जिसका बुकिंग होता है, वह है बिजनेस क्लास। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों की एक्सपेंडिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है।

मैडम, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, 144 करोड़ लोग हैं और बेरोजगारी का परसेंटेज उन्होंने बताया, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उन्होंने बोला कि 83 परसेंट लोग बेरोजगार हैं। 83 परसेंट लोग बेरोजगार कैसे हो सकते

हैं, मैडम? फिर, यह देश कैसे चलेगा, यह देश कैसे चल रहा है? इतनी सारी फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? यह जो इतने सारे फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स की बिक्री हुई, उन्हें किसने बनाया है? मैडम, मैं यह मानता हूँ कि उनको थोड़ा-सा आत्म-परीक्षण करने की जरूरत है।

मैडम, बेरोजगारी की बात करते हुए मैं यह पटल पर रखना चाहता हूँ कि जो लोग ईपीएफ भरते हैं, जो पेंशन फंड भरते हैं, वे 2014 में 11 करोड़ थे। 2014 में हमारे देश में ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड भरने वालों की संख्या 11 करोड़ थी, आज हमारे देश में प्रोविडेंट फंड भरने वालों की संख्या 28 करोड़ है। मतलब, इन 10 सालों में 17 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड भर रहे हैं, जिनको जॉब मिली है। जो अनऑर्गनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी संख्या इनसे दोगुनी है। फिर भी, ये यहां पर बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है।

मैडम, हमारा एक गवर्नमेंट PSU, HAL, यानी Hindustan Aeronautics Limited है, यह हम सब जानते हैं। वह 2014 से पहले बंद था, वहां पर आंदोलन चल रहे थे, वहां सैलरी नहीं मिल रही थी। वहां 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, उनके पास कोई आर्डर नहीं था। आज उनके पास डिफेंस के काफी ऑर्डर्स हैं। हम सब जानते हैं कि हम डिफेंस का करीबन 70 फ़ीसदी सामान बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हमारी स्थिति यह है कि हम 96 परसेंट इंडीजीनस बन चुके हैं और हम विदेशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। मैं HAL का इसलिए जिक्र कर रहा था, क्योंकि आज HAL के पास अगले 5 साल के आर्डर्स हैं। आज हमारे देश में डिफेंस के लिए MiG विमान बनाए जा रहे हैं, Hawk बनाए जा रहे हैं और Sukhoi जैसे विमान भी हमारे देश में निर्मित हो रहे हैं। जो choppers और हेलिकॉप्टर्स होते हैं, उनमें ध्रुव, चीता और चेतक जैसे choppers हमारे देश में इंडीजीनयसली बन रहे हैं। INS Vikrant इतना बड़ा जहाज है कि उसके ऊपर पांच हवाई जहाज उतरते हैं। INS Vikrant भी 100 प्रतिशत इंडीजीनयसली हमारे देश में बना, उसे हमारे लोगों ने बनाया और ये बोल रहे हैं कि यहां पर बेरोजगारी है!

मैडम, अब मैं किसानों की बात करना चाहूंगा। उन्होंने किसानों के बारे में कहा कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से आता हूँ, मैं सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करूंगा। अभी कोऑपरेटिव मंत्री यहां पर बैठे थे। PACS के लिए पहली बार सहकारिता मंत्रालय ने कुछ किया है। पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई है। हमारे नेता अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ। उन्होंने कई सारे कोऑपरेटिव्स को जीवन दान देने का काम किया।

मैडम, मैं शुगर इंडस्ट्री से भी आता हूँ, इसलिए मैं शुगर इंडस्ट्री की भी बात करूंगा। पिछले 25-30 सालों से शुगर इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ था और वह संकट इनकम टैक्स का था। जो शुगरकेन क्रश होता था, जो शुगर बनती थी, उसमें शुगरकेन की पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होता था, उसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स किसानों को देते थे। इसी के लिए इनकम टैक्स वालों ने उनको नोटिस दिया कि आप यह जो ऊपर का पैसा किसानों को देते हैं, वह आपका प्रॉफिट है और वह टैक्सेबल है, जिसके बाद उनके पास टैक्स के नोटिसेज़ आए। एक-एक फैक्टरी को सौ-सौ, दो-दो सौ और तीन-तीन सौ करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिसेज़ दिए गए थे। जब अमित भाई ने सहकारिता मंत्रालय संभाला तो उन्होंने सबसे पहला और सबसे बड़ा निर्णय यह लिया कि देश के सभी कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज़ को इनकम टैक्स के जो नोटिसेज़ मिले

थे, उनके 10,000 करोड़ रुपये माफ करने का काम किया। मैडम, PACS, यानी जो Primary Agricultural Cooperative Credit Societies हैं, वे हर गांव में दो-तीन हैं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, please conclude.

श्री धनंजय भीमराव महादिक: मैडम, दो-तीन मिनट दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती एस.फान्गनॉन कोन्याक): ठीक है, एक मिनट।

श्री धनंजय भीमराव महादिक: उनको मजबूत करने के लिए अभी 27 किस्म के अलग-अलग प्रोविजंस किए गए हैं और वे अब अलग-अलग बिजनेस कर सकते हैं। वे पेट्रोल पंप चला सकते हैं, गैस स्टेशन बना सकते हैं, वेयरहाउसिंग चला सकते हैं, डेयरी चला सकते हैं, जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ये सब नया है और केंद्र सरकार की तरफ से उनको इसके लिए पूरा समर्थन मिलने वाला है।

मैडम, अब मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। हमारे साथी सदस्य महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे थे कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। मैं आपको यहां पर दो-चार आंकड़े गिनवाना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जो वधावन पोर्ट बन रहा है, उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए केंद्र से दिया गया है। मुंबई मेट्रो के लिए 1,087 करोड़ और मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 908 करोड़ दिए गए हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र rural roads के लिए 400 करोड़ रुपये, Mumbai-Delhi Industrial Corridor के लिए 499 करोड़ रुपये, कृषि प्रकल्प के लिए 598 करोड़ रुपये, ...(**समय की घंटी**)... मैडम, इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 466 करोड़ रुपये, MMR Green Urban Mobility के लिए 150 करोड़ रुपये, नागपुर मेट्रो के लिए 683 करोड़ रुपये, नाग नदी के लिए 500 करोड़ रुपये, पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़ रुपये, मुला-मुथा रिवर के लिए 690 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 15,940 करोड़ रुपये दिए हैं। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Next speaker is Shri Ravi Chandra Vaddiraju. ...*(Interruptions)*...

श्री धनंजय भीमराव महादिक: मैडम, मैं समाप्त कर रहा हूं। पोषण अभियान के लिए 1700 करोड़ रुपये। ...(**व्यवधान**)... मैडम मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। ... मैडम, हमारे विपक्ष के कुछ साथी बोल रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी का यह आखिरी भाषण है। मैं उस पर कहना चाहता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है।

"ज़िन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है
हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है

अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन,
आगे तो सारा आसमान बाकी है।"

जय-हिन्द, जय-महाराष्ट्र!

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, Shri Ravi Chandra Vaddiraju to speak in Telugu.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): †"Hon. Vice-Chairperson, I convey my heartfelt thanks and gratitude for the opportunity to speak on the budget presented by the Central Government for the financial year 2024-25. On behalf of the BRS party, I congratulate the Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman for record seventh consecutive Budget presentation. It is known to all that the State of Telangana has witnessed inclusive development in all fields, which is possible only with the vision of its first Chief Minister, Shri KCR. Telangana has been on the path of progress in the short span of 10 years. If the Central Government extends more support to such a progressive state, it will contribute more to the country's economic development.

The people across the country believe that Telangana has a peaceful environment and better law and order. Industrialists, companies, educational institutions, hospitals, investors, and people coming for livelihood are also preferring Hyderabad. This shows, this is a milestone for the development made by the first Chief Minister of Telangana, Shri KCR, in the last ten years. The people of Telangana are slowly realizing what they have lost. They lost self-governance and became slaves to the big-wigs of Delhi. Telangana is being treated like a neglected child, as there is no mention of Telangana in the Budget and no funds are allocated to the State. The State of Telangana which has a representation of two Cabinet Ministers and eight BJP MPs in the Union Government did not receive anything in the budget. People believe that a flood of funds to Andhra Pradesh and mud has flown to Telangana. Telangana BJP MPs claim that they are successful in bringing excess funds to the State. However, these funds are routine funds that are allocated to every State in the budget. Telangana BJP MPs should confess to the people that they are not successful in drawing more funds to the State. For the first time after the birth of the BJP party, eight BJP MPs were elected from Telangana. However, people are warning that, if this disparity in allocation of funds continue. it will not only be their first budget but also their last budget presentation.

---

† English translation of the original speech delivered in Telugu.

We are happy that the neighbouring State of Andhra Pradesh was allotted more funds. We are neither jealous nor do we envy. Sadly, the children of Telangana are not getting even a single rupee. Our party's struggle is for the development of Telangana and the development of its people. Congress and BJP MPs should answer the people for failing to get funds for Telangana. The MPs should fight to get more funds from the Centre. The words spoken by hon. KCR in the past Assembly and Parliament elections are now being experienced by the people as literal truths. Had the BRS Party won maximum number of MP seats in Telangana, the situation would have been very favourable in both the Centre and the State today. The States of Andhra Pradesh and Bihar are examples of this. If the national party is in power in small states, the respective MPs will work on personal agenda and not fight for the cause of the State. Today's situation would not have arisen if more MPs were elected from the BRS Party, which was established for the cause of development of Telangana.

On behalf of the BRS party, I appeal to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi to respond positively to the fair demands of the people and allocate more funds to the State. Palamuru-Rangareddy Irrigation Scheme should be awarded national status and allocate large amount of funds. Mamnoor Airport should be modernized and civil aviation flights should be started. Measures should be taken to construct green field airports at Kottagudem, which is a few kilometres away from the temple Bhadrachalam, which is the second biggest temple for Lord Ram after Ayodhya in the country.

In the Hyderabad-Bangalore industrial corridor, more industries should be set up in Telangana. We also request to give financial assistance to the backward district of Mahabubnagar district which falls along this corridor. Special funds should be earmarked for the development of backward districts. A National Horticulture University should be established and the National Institute of Design (NID) should also be established. A mega power unit should be set up to support weavers and handloom workers. A Mega Textile Park like the one at Surat should be established, the handloom sector should be further encouraged and weavers should be supported. All our demands are mentioned in the Andhra Pradesh Reorganization Act. The AP Reorganization Act was not only for the establishment of institutes in Andhra Pradesh but also for Telangana. Coal mines should be allotted to the Singareni Collieries Company Limited (SCCL). The SCCL is a government company. Telangana has a fifty-one per cent share while the Central Government has forty-nine per cent. It is not a private company. It is a Government company. The Central Government should allot the Sravanapalli coal mining block to public sector coal

miner, Singareni Collieries Company Limited and also other coal mines should be allotted as per Section 11 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act. I request the hon. Prime Minister, to establish IIT and IIM in Telangana as mentioned in The Andhra Pradesh Reorganization Act. A railway coach factory should be established in Kazipet. You are giving three crore houses in the next five years. We want to give one twenty-five lakh houses out of it. Defence Lands be transferred. Shri KCR wrote several letters to the Central Government in this regard. The Central Government should set up the Bayyaram steel factor as mentioned in the Andhra Pradesh Reorganization Act. Funds should be allotted for Regional Ring Road. Tenders should be called for this project. The State Highways in Telangana should be converted to National Highways. Navodaya Vidyalayas should be established in all 33 districts of Telangana. Thank You, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Member, Shri Neeraj Shekhar; ten minutes.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय वाजपेयी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आज अभिवादन करना चाहता हूं इस देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी का कि वे तीसरी बार प्रधान मंत्री बने और इस देश की महान जनता का वंदन करता हूं कि उन्हें तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाया। मैं उनको इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, जो इस देश की समस्या को जानता है। इस देश में जो कठिनाइयां हैं, जो इस देश के किसानों की समस्या है, इस देश के मजदूरों की समस्या है, उनको जानता है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दस सालों में जो काम हुए हैं, उससे यह दिखता है कि जो काम आजादी के बाद होने चाहिए थे, उसको 65 साल लग गए। आप जानते हैं कि आजादी के बाद हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी। हमारी प्राथमिक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। उस समय के जो नेता थे, उनकी प्राथमिकता और थी। उनकी प्राथमिकता इस देश का आम आदमी नहीं था, इस देश का किसान नहीं था। मुझे दस मिनट का समय मिला है, मैं दो-चार बातें कहना चाहूंगा। जो मेरे हृदय के सबसे पास है, वह सबसे ज्यादा जरूरी, जिसको 70 साल लग गए, वह यह है कि हम इस देश को स्वच्छ पानी नहीं दे पाए। जल-जीवन मिशन, 70 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति आया, जिसने इस देश के पानी की समस्या को समझा। इस देश के गांव में जो व्यक्ति रहता है, उसकी समस्या को जानने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य है, अभी हमारे कांग्रेस के साथी नहीं हैं, फिर भी मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कभी यह ख्याल नहीं आया कि ऐसी योजना लाई जाए, हर घर नल से जोड़ा जाए। मैं इसलिए इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जब यह योजना शुरू हुई थी, तब सिर्फ तीन करोड़ परिवारों में पानी

पहुंचता था, आज करीब 14-15 करोड़ परिवारों में पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में हर घर में नल से जल पहुंचेगा।

यह हम लोगों की प्राथमिकता है, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने इस देश को देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो गांव-गांव गया है, उसने देखा है कि यह देश की समस्या थी। जहां पानी नहीं मिलता था, वहां पर हमारी माताओं, बहनों को कई किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि हर घर तक नल से पानी पहुंचे। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना बनाई गई। मैं प्रधान मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी को बधाई देना चाहूंगा कि वे ऐसी योजना लेकर आए। हम विश्वभर में इस योजना की कहीं तुलना नहीं कर सकते। इसको वही व्यक्ति ला सकता है, जो इस देश के गरीब की पीड़ा को जानता होगा। मैंने देखा है, हमारे कई साथियों ने देखा होगा, क्योंकि हम लोग पुछार करने जाते हैं। कभी किसी के घर में कोई मर जाता है या किसी का देहांत हो जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है, तो हम उनके घर में जाते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. भागवत कराड़)** *पीठासीन हुए।*]

हमने कई बार देखा है कि लोगों ने इलाज कराने के लिए घर बेच दिया है, खेत बेच दिए हैं। इस पीड़ा को अगर कोई जानता था, तो माननीय प्रधान मंत्री जी जानते थे। इसीलिए वे आयुष्मान योजना लेकर आए कि हम पांच लाख रुपयों से गरीब की मदद करें। यह कोई छोटी रकम नहीं है। इससे 55 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। इसके लिए बजट में जो एलोकेशन हुआ है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। 70 साल की उम्र के लोगों को इससे जोड़ा गया है। कुछ जरूरी चीज़ें हैं, जिनको मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं। हमारे कई साथियों ने मनरेगा की बात कही है। मैं जानता हूं कि मनरेगा आपके समय में आया था और आप ही लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और बार-बार कहते हैं कि इसका बजट कम कर दिया गया है। यह डिमांड ड्रिवेन है। जब भी इसके लिए जितनी आवश्यकता होगी, उतना यह सरकार देगी। यह कानून आप लोगों ने बनाया है और आप ही इसके बारे में नहीं जानते हैं। आप बार-बार इस बात को दोहराते हैं। इस देश के पूर्व वित्त मंत्री जी इस बात को दोहराते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपनी ही चीजों को नहीं जानते हैं।

स्वच्छ भारत - जब मैं उस तरफ बैठता था, तब भी माननीय प्रधान मंत्री जी की इस योजना के लिए बधाई देता था। मुझे आज भी याद है 2 अक्टूबर, 2014 में जब उन्होंने यह योजना शुरू की थी, तो पूरा देश उसका मजाक उड़ा रहा था। यह सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था कि इस देश में स्वच्छता हो, शौचालय बने। हमारे मित्रों ने उनके नाम पर वोट तो बहुत लिए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया। उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का अगर किसी ने सपना पूरा किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ था। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं, वे जानते हैं कि 2014 के पहले, अगर आप शाम को सड़क से निकल जाते थे और गाड़ी की लाइट जलती थी, तो हम अपनी आंखें शर्म से नीचे कर लेते थे। हमारी माताओं और बहनों के लिए उन्होंने काम किया है। आज बजट में उसके लिए 7 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर घर में शौचालय बने। पिछले दस साल की सरकार में यह काम हुआ है।

मैं आवास की बात करना चाहूंगा। 2014 तक कितने आवास बने? मैं तो चाहूंगा कि हमारी वित्त मंत्री जी बताएं कि पिछले 65 सालों में कितने आवास बने? मैं जानता हूं कि हमारी सरकार में हम लोगों ने 4 करोड़ आवास बनाए हैं। जैसे ही हम तीसरी बार आए, हमने तय किया कि हम गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ आवास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे। हमने शहरी आवास दिया है, उसके लिए अलग से बजट है।

हमें कहा जाता है कि हम अल्पसंख्यक के विरोधी हैं। अगर शहरी आवास योजना से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है, तो हमारे मुसलमान भाइयों को हुआ है और इसके लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। अगर हम चाहते, तो हम इस योजना को बंद कर देते। मगर हमारी सरकार, हमारा नेता कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक समान है। इस बजट में कई योजनाएं ऐसी हैं, जैसे प्रधान मंत्री किसान योजना। मैं इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। हमारे मित्र 6 हजार रुपये, 6 हजार रुपये कहते हैं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के साथी कभी 6 हजार की कीमत नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो लाखों-करोडों के घोटाले करने वाले लोग हैं। इनको 6 हजार की कीमत समझ में नहीं आयेगी। 6 हज़ार रुपये एक किसान के लिए क्या हैं, आप यह उस किसान से, उस गरीब व्यक्ति से जाकर पूछिए कि उसके लिए 6 हज़ार की कीमत क्या है।

महोदय, विकसित भारत यात्रा निकली थी, हम लोग उसमें गए थे और जब हम किसानों से पूछते थे, तो कई किसान कहते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कई कहते थे कि हम खाद खरीद रहे हैं, कई कहते थे कि बीज खरीद रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस राशि को और बढ़ाया जाए। मैं इसको बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा।

महोदय, मैं अपने साथियों से, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह योजना पहले नहीं आ सकती थी? 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' और 'आयुष्मान भारत योजना' जैसी योजनाएं पहले क्यों नहीं आ सकती थीं? ऐसी योजनाएं क्यों नहीं आ सकती थीं, जो सीधे एक आम आदमी को, एक किसान को फायदा पहुंचाती थीं? क्या पहले पैसा नहीं था? सरकारों के पास पहले भी पैसा था, आपको पैसा लाना चाहिए था और ऐसी योजनाओं में लगाना चाहिए था। आपने पैसा क्यों नहीं लगाया? मैं अपने विपक्ष के साथियों के पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं किसान के लिए ऐसा किया? आप किसान के लिए हमेशा कहते हैं कि अन्नदाता है, लेकिन आप यह बताएं कि आपने अन्नदाता के लिए क्या किया? आप लोग कहते हैं कि एक बार ऋण माफी की थी। आप 72 हज़ार करोड़ कहते हैं, लेकिन आपने किसानों को 50 हज़ार करोड़ से कम दिया है। हम तो 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' में ...(**व्यवधान**)... आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इन्हें बताएं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दे चुके हैं। आप ऐसी योजना लेकर क्यों नहीं आए? जब आप सत्ता में थे, पैसा तो तब भी था, लेकिन वह पैसा 2G, 3G और कॉमनवैल्थ में चला जाता था। ...(**व्यवधान**)... मैं वह बोलना नहीं चाहता, उसकी तो एक लिस्ट थी। ...(**व्यवधान**)... करीब 52 घोटालों की लिस्ट थी। ...(**व्यवधान**)...

डा . सैयद नासिर हुसैन: कोर्ट ने क्या बोला?

श्री नीरज शेखर: कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट तो कई चीजें बोल चुका है। मैं आग्रह करूंगा ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Neeraj*ji*, you have to conclude. Only 20 seconds are remaining.

श्री नीरज शेखर: महोदय, मैं अपने भाषण का अंत करना चाहता हूं। मैं जानता था कि मेरा 10 मिनट का समय है। ये सब काम पिछली सरकारों में हो सकते थे, लेकिन उनकी इच्छाशक्ति नहीं थी। मैं हमेशा इस बात को बार-बार इसलिए दोहराता हूं, क्योंकि एक गरीब की पीड़ा, एक किसान की पीड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है, जो उस दौर से गुज़रा हो। महोदय, मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम लोग भूख क्या समझोगे। आज मैं वह बात स्वीकार करता हूं। आज हमें जब भूख लगती है, तो हम कैंटीन में चले जाते हैं, वड़ा खा आए, डोसा खा आए, लेकिन मैं भूख की पीड़ा तब समझ सका, जब आज से 12 साल हमारे क्षेत्र में पहले एक व्यक्ति भूख से मर गया। उसने दो दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए वह भूख से मर गया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude.

श्री नीरज शेखर: महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि पीड़ा वही समझ सकता है, जो उस दौर से गुज़रा हो। माननीय प्रधान मंत्री जी उस दौर से गुज़रे हैं। वे इस देश में घूमे हैं। लोग बार-बार कहते हैं कि सूट-बूट की सरकार और बड़ी सरकार। यह व्यक्ति इस देश में स्कूटर और मोटर साइकिल पर घूमा है, यह व्यक्ति बसों में घूमा है, ट्रेन में घूमा है, इसलिए वह समझ सकता है।...(**समय की घंटी**)...सर, मैं तो रेल पर पहुंचना चाहता था, कई लोगों ने रेल पर बोला है, लेकिन मैं अंत में अपना एक व्यक्तिगत अनुरोध माननीया वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। मैं सदन में पिछले 16-17 सालों से यह बात बार-बार सुनता आया हूं और मुझे पीड़ा होती है। मुझे यह पीड़ा इसलिए होती है, क्योंकि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं, जब लोग कहते हैं कि 1990-91 में, जब मेरे पिताजी प्रधान मंत्री थे, तो इस देश का सोना बेच दिया था, सोना गिरवी रख आए। यह बात कई बार कही जाती है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा, उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय, जब मेरे पिताजी, पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी थे, तब क्या यह उनके आठ महीने की वजह से था या उनसे पहले जो सरकारें थीं, जो 80 के दशक की सरकारें थीं, उनके कारण था। मैं यह बात बार-बार कहना चाहता हूं। मैंने हर वित्त मंत्री से यह अनुरोध किया है और मैं यह अनुरोध फिर से इसीलिए करना चाहता हूं कि इस पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि इसका क्या कारण था। जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संकट का काल था, यह उस समय का वाकया था। महोदय, उस पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)...मैं यही अनुरोध और विनती करना चाहता हूं। मैं फिर से अपने सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Now, next speaker is Shri Tejveer Singh; you have to complete your speech within 10 minutes.

श्री तेजवीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे आम बजट के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने सदन के नेता और जो हमारे चीफ व्हिप हैं, श्रीमान लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं दो दिन से पीछे पड़ रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिले, लेकिन आज उन्होंने मेरी सुन ली।

मान्यवर, यह लगातार तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। यह कहा जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो सामने बैठे हैं कि पहले भी गठबंधनों की सरकारें रही हैं। इनके इतने दलों से गठबंधन थे। आज ये अपने इंडिया गठबंधन को मान लेते हैं और हमारे गठबंधन को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। देश की जनता ने तीसरी बार सरकार बनवाई और देश के गौरव माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार देश की जनता ने मौका दिया। एक ऐसे प्रधान मंत्री, जिन्होंने गरीबी देखी हो, जो प्लेटफॉर्म पर दौड़ा हो, गरीबी में जीवनयापन किया हो, ऐसे प्रधान मंत्री को मौका दिया गया। आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी आम बजट - 2024-25 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि दिखाई देती है। इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, समय, समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प दिखाई पड़ता है। यह हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए, प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा स्वागतयोग्य है। नए भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करते, इस लोककल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं तहेदिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण बजट में आपके सामने खड़ा होकर कृषि बजट के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। चूँकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और मेरा यह भी सौभाग्य रहा है कि राजनीति में मेरी शुरुआत किसानों से संबंध रखने वाली संस्था से हुई।

मैं चार बार डिस्ट्रिक्ट कॉओपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश कॉओपरेटिव बैंक का भी चेयरमैन बना। किसानों को क्या दुख है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, यह मैं भली-भांति जानता हूं, लेकिन हमारे सामने बैठे हुए मित्र हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक महान नेता जो पूर्व प्रधान मंत्री थे, स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उस नारे का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 60 से 65 साल तक ये सरकार में रहे। ये उस नारे को भूल गए, शास्त्री जी जैसे महान नेता को भूल गए। उस नारे पर इनका ध्यान नहीं गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीमा पर जो सीने पर गोली खाने वाला नौजवान होता है, वह कोई और नहीं होता है, वह किसान का बेटा होता है। किसान के लिए कोई काम नहीं किया गया और न ही उन शहीद परिवारों पर कोई ध्यान दिया गया। यह शुरुआत 1996 के बाद जब माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधान मंत्री बने, उस समय से शहीद को सम्मान देने का काम शुरू हुआ। पहले शहीद के मां-बाप अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाते थे। आज किसी मां का लाल शहीद होता है, तब मां-बाप क्या, पूरा क्षेत्र उसके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है। तिरंगा झंडा फैलाया जाता है, जिले का कलेक्टर और एसएसपी उसे सलामी देने जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग उस शहीद को श्रंद्धाजलि देकर अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई देते हैं। पहले उस ओर ध्यान नहीं गया। किसान को बरबाद करने का काम इन लोगों ने किया।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसान के लिए विकास का कोई रास्ता नहीं सुझाया। उसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इस ओर इनका ध्यान नहीं गया। हां, एक रास्ता सुझाया। किसान को आत्महत्या करने का रास्ता इनके ही द्वारा दिखाया गया। आज किसानों की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, वह इनकी ही देन है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कई योजनाओं की शुरू की हैं। 2024 के कृषि बजट में हमारी सरकार ने 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष 2023 के बजट से 27 हज़ार करोड़ अधिक है। इससे कृषि विकास को बड़ी गति मिलेगी। मोदी जी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं को शुरू किया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। उन्होंने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सुरक्षा बीमा योजना, कृषि और भूमि सुधार योजना जैसे अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। कृषि ऋण कार्ड योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी बात नीरज जी ने बढ़ाने की है, मैं भी उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं, लेकिन प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि जो है, हमें यह खुशी हो रही है कि ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Tejveerji, you have to conclude in 30 seconds, because we have to complete it by 8.00 p.m.

श्री तेजवीर सिंहः इसे 6 हज़ार से 12 हज़ार कर दिया गया है। मान्यवर, मैं कुछ समय और लूंगा। मैं ग्राम विकास पर जरूर बोलना चाहता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और हमारा किसान ग्राम से जुड़ा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. भागवत कराड़): हमें 8 बजे खत्म करना है। कृपया जल्दी करें।

श्री तेजवीर सिंहः मान्यवर, आज ग्राम शहर दिखाई देते हैं। जो पलायन शहरों को हो रहा था, आज ग्राम इतने सुविधायुक्त हो गए हैं कि अब शहरों से ग्रामों की ओर पलायन होगा, ऐसा प्रतीत होने लगा है। मान्यवर, विश्व में हमारी सबसे ज्यादा GDP growth है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude, Tejveer *Sahab.* *...(Interruptions)...*

श्री तेजवीर सिंह: मान्यवर, मैं दो मिनट लूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. भागवत कराड़): दो मिनट टाइम नहीं है, और दो speakers हैं। There is a message from Lok Sabha also.

श्री तेजवीर सिंह: मान्यवर, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude. I am calling the next speaker. There is no time. *...(Interruptions)...*

श्री तेजवीर सिंह: जी, सर। इन्होंने MSP के बारे में बताया था और MSP को लेकर शोर मचा। मैं इनके समय की बात कहना चाहता हूँ कि इनके समय में 2012-13 में धान का समर्थन मूल्य 1,250 था, 2024-25 में यह 2,040 हुआ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): There are two more speakers. I am calling the next speaker. *...(Interruptions)...*

श्री तेजवीर सिंह: सर, मैं एक सेकंड लूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. भागवत कराड़): आप एक सेकंड नहीं, 5 सेकंड लीजिए।

श्री तेजवीर सिंह: गेहूँ का समर्थन मूल्य 1,350 था, अब गेहूँ का समर्थन मूल्य 2024-25 में 2,300 किया गया है। ज्वार का समर्थन मूल्य 1,500 था ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude. I am calling the next speaker. *...(Interruptions)...*

श्री तेजवीर सिंह: हमारी सरकार में 3,050 किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा समर्थन मूल्य बहुत अच्छा है, इनसे दोगुना है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री तेजवीर सिंह: भविष्य में हमारी सरकार यह गारंटी दे रही है कि किसान के माल को कोई सस्ती दर पर खरीदने की कोशिश करेगा, तो सरकार उस माल को खरीदने का काम करेगी। अंत में, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Thank you, Tejveer Singh*ji*. There is a message from Lok Sabha. Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 3) Bill, 2024

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 30th July, 2024, passed the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 3) Bill, 2024.

The Speaker has certified that the Bill is a Money Bill.

I lay a copy of the said Bill on the Table.

GENERAL DISCUSSION-*Contd.*

The Union Budget, 2024-25
and
The Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2024-25

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BHAGWAT KARAD): Next speaker is Shri Ryaga Krishnaiah. You have three minutes.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman Sir, the Union Budget is a routine Budget, with routine schemes. There are no schemes, particularly for OBCs. The reservation to OBCs was provided 34 years back. Still, there is no financial assistance to OBC students. Without financial support, how will they study, more particularly in IIMs, IITs, and other central educational institutes?They have been provided with 27 per cent reservation.There is also a restriction of Creamy Layer. Those who are below Creamy Layer, how will they study if they are to pay huge amount of fees? In IIMs, the fee is nearly two lakh rupees, plus there are